नई दिल्ली ■ शनिवार 09 मई 2026 ■ मूल्य 5.00 ■ वर्ष 14 ■ अंक 41 ■ पृष्ठ 08

JBT जनभावना टाइम्स

www.thejbt.com

निष्पक्ष और निर्भीक खबर

दिल्ली, गौतमबुद्ध नगर, देहरादून, लखनऊ, अलीगढ़, मथुरा, हिसार, कैथल, करनाल एवं मुजफ्फरनगर से प्रकाशित

04 पढ़ाई तो बढ़ी... लेकिन स्किल क्यों नहीं ? | 07 ग्लोबल शतरंज लीग का चौथा सत्र भारत में होगा | दो बड़ी फिल्मों की रिलीज को लेकर चर्चा तेज 08

शुभेंदु अधिकारी होंगे बंगाल के नए सीएम

अमित शाह की मौजूदगी में चुने गए भाजपा विधायक दल के नेता

कोलकाता। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस प्रमुख व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को शिकस्त देने वाले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता शुभेंदु अधिकारी को विधायक दल का नेता चुना गया है। शुक्रवार को आयोजित विधायक दल की बैठक में यह फैसला सहमति से लिया गया।

भाजपा के विजयी 207 उम्मीदवारों के साथ बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य पर्यवेक्षक के रूप में उपस्थित रहे। उनके साथ ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी सहायक पर्यवेक्षक के तौर पर उपस्थित थे। नई सरकार का शपथ ग्रहण शनिवार को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। कोलकाता के न्यू टाउन स्थित विश्वा बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में हुई बैठक में मुख्यमंत्री माझी ने भाजपा के विजयी विधायक के साथ बैठक की। वहां सर्वसम्मति से संसदीय दल के नेता के साथ-साथ मुख्यमंत्री के तौर पर शुभेंदु अधिकारी का नाम तय किया गया। शुभेंदु शुक्रवार को ही लोकभवन जाकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। बंगाल के

राजनीतिक गलियारों में पिछले कई दिनों से शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने की चर्चा तेज थी। विधानसभा चुनाव में उनके प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें मुख्यमंत्री पद का सबसे प्रबल दावेदार माना जा रहा था। 2021 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने ममता बनर्जी को नंदीग्राम में शिकस्त दी थी। वहीं, इस बार के चुनाव में शुभेंदु ने ममता के गढ़ भवानीपुर में उन्हें चुनौती दी और कामयाबी हासिल की। नंदीग्राम और भवानीपुर दोनों सीटों पर मिली कामयाबी ने मुख्यमंत्री पद के लिए शुभेंदु की दावेदारी को और मजबूत कर दिया था। अब सभी की नजरें शनिवार को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह पर टिकी हैं, जहां नए मंत्रिमंडल की तस्वीर साफ होने की उम्मीद है।

घोषणापत्र में किये गये सभी वादों को पूरा करेंगे : शुभेंदु

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री पद के लिए नामित किए गए शुभेंदु अधिकारी ने शुक्रवार को कहा कि राज्य में नई और पहली भाजपा सरकार पार्टी के चुनाव घोषणापत्र में किए गए सभी वादों को पूरा करेगी और लोगों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए केंद्र के साथ मिलकर काम करेगी। भाजपा विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद पार्टी विधायकों को संबोधित करते हुए अधिकारी ने कहा कि बंगाल में डर का माहौल खत्म हो गया है और राज्य अब 'भरोसे' के दौर की ओर बढ़ेगा। पार्टी विधायकों और समर्थकों की ज़ोरदार तालियों के बीच अधिकारी ने कहा, "भय अब खत्म हो गया है और जैसा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने कहा है, भरोसा आ गया है।" इससे पहले अधिकारी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रदेश में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की मौजूदगी में सर्वसम्मति से भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया, जिससे उनके पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया।

ममता बनर्जी सोशल मीडिया प्रोफाइल से 'मुख्यमंत्री' शब्द हटाने को तैयार नहीं

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजनीति में सत्ता परिवर्तन की चर्चाओं के बीच तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी एक बार फिर राजनीतिक बहस के केंद्र में आ गई हैं। इस समय वह मुख्यमंत्री पद पर नहीं हैं, लेकिन उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल पर अब भी उनकी पहचान 'मुख्यमंत्री' के रूप में दर्ज है। इसे लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में नई बहस शुरू हो गई है।

अधिकारी ने राज्यपाल से मिलकर पेश किया सरकार बनाने का दावा

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद के लिए नामित शुभेंदु अधिकारी ने शुक्रवार शाम राज्यपाल आर एन रवि से मुलाकात की और राज्य में भाजपा के नेतृत्व वाली पहली सरकार बनाने का दावा पेश किया। अधिकारी भाजपा की प्रदेश इकाई के दिलीप घोष, लॉकेट चटर्जी और तापस रॉय सहित कई शीर्ष नेताओं के साथ लोकभवन पहुंचे। इससे पहले अधिकारी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई बैठक में भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। हाल में संपन्न हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 294 सीट में से 207 सीट जीतकर विजय पताका फहराई, जबकि तृणमूल कांग्रेस केवल 80 सीट पर सिमट गई। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, शीर्ष केंद्रीय मंत्रियों और भाजपा शासित राज्यों के लगभग 20 मुख्यमंत्रियों की उपस्थिति में शनिवार को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में एक भव्य समारोह में अधिकारी और उनकी मंत्रिपरिषद का शपथग्रहण होगा।

सोमनाथ मंदिर हमारी सभ्यता का अटूट संकल्पः पीएम मोदी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के लोकार्पण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 11 मई को उन्हें एक बार फिर वहां जाने का सौभाग्य मिलेगा। उन्होंने इसे भारत की सभ्यता और आस्था की महानता का प्रतीक बताया और उन विभूतियों एवं वीरों को नमन किया जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी सोमनाथ की रक्षा की और उसकी शान को पुनर्जीवित किया।

प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पोस्ट में सोमनाथ पर लिखे अपने लेख को साझा करते हुए कहा कि यह अवसर हमें स्मरण कराता है कि इस पावन स्थल की रक्षा और इसके पुनर्निर्माण के लिए देश की कई पीढ़ियों ने निरंतर संघर्ष किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि हमारी सभ्यता का अटूट संकल्प है। समुद्र की लहरें हमें यह सिखाती हैं कि चाहे कितने भी तूफान क्यों न हों, मनुष्य का साहस और आत्मबल हर बार फिर से उठ खड़ा होने में सक्षम है। प्रभास की परिक्रमा पूरी पृथ्वी की परिक्रमा के समान है और यहां आने वाले श्रद्धालु उस सभ्यता की अद्भुत निरंतरता का अनुभव करते हैं, जिसकी ज्योति कभी बुझाई नहीं जा सकी। प्रधानमंत्री ने उन असंख्य विभूतियों का स्मरण किया जिन्होंने आक्रमणों के बीच भी सोमनाथ की रक्षा की। प्रधानमंत्री ने लकुलीश और सोम शर्मा जैसे मनीषियों से लेकर महाराज धारसेन चतुर्थ, भीम प्रथम, जयपाल, आनंदपाल, राजा भोज, कर्णदेव सोलंकी, जयसिंह सिद्धराज, कुमारपाल सोलंकी, भाव बृहस्पति, पाशुपताचार्य, विशालदेव वाघेला, त्रिपुरांतक, महिपाल चूड़ासमा, राव खंगार चूड़ासमा और पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होल्कर सहित अनेक नामों का जिक्र करते हुए कहा कि इन सबने कठिन समय में भी भक्ति और परंपरा को जीवित रखा। उन्होंने वीर हमीरजी गोहिल और वीर वेगड़ाजी भील जैसे पराक्रमियों को भी नमन किया।

प्रधानमंत्री ने अपने लेख में महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सरदार बल्लभ भाई पटेल के योगदान को याद करते हुए कहा कि 13 नवंबर 1947 को सरदार पटेल ने सोमनाथ के जर्जर अवशेषों के सामने समुद्र का जल हाथ में लेकर यह प्रतिज्ञा की थी कि सोमनाथ का पुनर्निर्माण होगा। दुर्भाग्यवश वह इस सपने को साकार होते नहीं देख सके, लेकिन उनके विजन को केएम मुंशी ने आगे बढ़ाया और 1951 में मंदिर का पुनर्निर्माण पूरा हुआ। राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने उद्घाटन समारोह में भाग लेकर इसे ऐतिहासिक बना दिया, जबकि तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने इसका विरोध किया था। उन्होंने कहा कि उन्हें अक्टूबर 2001 का वह समय याद है जब मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने दायित्व संभाला था। उसी वर्ष सरदार पटेल की जयंती पर सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 50वीं वर्षगांठ का आयोजन हुआ था जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी भी उपस्थित थे।

उन्होंने डॉ. राजेंद्र प्रसाद के उस ऐतिहासिक भाषण का उल्लेख किया जिसमें कहा गया था कि सोमनाथ मंदिर दुनिया को यह संदेश देता है कि श्रद्धा और विश्वास को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक से देश 'विकास भी, विरासत भी' के मंत्र पर चल रहा है। सोमनाथ से काशी, कामाख्या से केदारनाथ, अयोध्या से उज्जैन और त्र्यंबकेश्वर से श्रीशैलम तक, सभी आध्यात्मिक केंद्रों को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया गया है।

संक्षिप्त खबरें

मणिपुर के सेनापति -चुराचांदपुर जिले से भारी मात्रा में हथियार एवं गोला-बारूद

इंफाल। राज्य में लगातार सुरक्षा बलों एवं पुलिस की कार्रवाई जारी है। राज्य के विभिन्न हिस्सों में जारी अभियानों में उग्रवादियों की गिरफ्तारी के साथ ही भारी मात्रा में हथियारों एवं गोला-बारूद के जखीरों की बरामदगी का सिलसिला जारी है। मणिपुर पुलिस मुख्यालय शुक्रवार को आधिकारिक बयान में बताया कि 07 मई को सुरक्षा बलों ने सेनापति जिले के सेनापति थानांतर्गत मारेमई-हेंगबुंग पहाड़ी इलाकों में अभियान चलाते हुए भारी मात्रा में हथियार एवं गोला-बारूद बरामद किया। बरामद सामग्रियों में दो प्वाइंट 22 बोर की राइफल मैगजीन के साथ, एक .303 बोर की राइफल मैगजीन के साथ, एक एमपी5 मैगजीन के साथ, एक एके-47 राइफल मैगजीन के साथ, चार स्थानीय तौर पर बनी बोल्ट एक्शन राइफलें, एक स्थानीय तौर पर बनी शॉटगन, तीन प्वाइंट 32 पिस्तौलें मैगजीन के साथ, दो प्वाइंट 22 बोर की पिस्तौलें मैगजीन के साथ, 79 अलग-अलग कैलिबर के जिंदा कारतूस और 13 अलग-अलग कैलिबर के खाली खोखे शामिल हैं।

भारत-सिंगापुर आतंकवाद और सीमा पार अपराध के खिलाफ सहयोग पर सहमत

नई दिल्ली। भारत और सिंगापुर ने आतंकवाद तथा सीमा पार अपराध के खिलाफ सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति जताई है। दोनों देशों ने आतंकवाद के सभी स्वरूपों की कड़ी निंदा करते हुए इसके खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' की नीति की बात दोहराई। भारत और सिंगापुर के बीच आतंकवाद एवं सीमा-पार अपराध से निपटने पर संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) की पांचवीं बैठक 7 मई को नई दिल्ली में आयोजित हुई। इस बैठक की सह-अध्यक्षता भारतीय विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव (आतंकवाद-रोधी) डॉ. विनोद बहादे और सिंगापुर के गृह मंत्रालय में उप सचिव (नीति) न्यियम शिह चुन ने की। संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, भारत और सिंगापुर ने रणनीतिक साझेदार के तौर पर आतंकवाद का मुकाबला करने में द्विपक्षीय सहयोग के महत्व पर जोर दिया। जेडब्ल्यूजी ने बैठक में सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की स्पष्ट और कड़े शब्दों में निंदा की और आतंकवाद के प्रति 'शून्य सहनशीलता' के सिद्धांत की पुनः पुष्टि की।

यौन अपराधों पर एनसीडब्ल्यू सख्त, पोक्सो मामले में पैरोल न देने की सिफारिश

नई दिल्ली। राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ गंभीर अपराधों में दोषी ठहराए गए अपराधियों को पैरोल दिए जाने पर गहरी चिंता जताई है। आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने कहा कि जल्द ही केंद्र सरकार को सिफारिश भेज कर रेप, गैंगरेप, गंभीर यौन उत्पीड़न और पोक्सो जैसे मामलों में दोषियों को पैरोल न देने की मांगी जाएगी। अध्यक्ष ने अपने बयान में कहा कि नसरापुर-भोर की घटना ने महिलाओं की सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। ऐसे मामलों में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, सम्मान और न्याय को सर्वोच्च प्राथमिकता मिलनी चाहिए। आयोग ने न्याय व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए केन्द्र सरकार को कई अहम सुझाव दिए हैं जिसमें महिलाओं और बच्चों से जुड़े मामलों के लिए स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना, जांच और ट्रायल में कानूनी विशेषज्ञों की मदद से बेहतर समन्वय, सबूतों की जांच, गवाहों के बयान और जांच प्रक्रिया को तय समय में पूरा करने के लिए अलग तंत्र, रेप और पोक्सो मामलों के आदतन अपराधियों पर कड़ी निगरानी शामिल है। आयोग ने यह भी कहा कि पोक्सो और अन्य यौन अपराधों में बार-बार शामिल होने वाले आरोपितों पर पुलिस की लगातार निगरानी होनी चाहिए। जरूरत पड़ने पर अच्छे व्यवहार के लिए बांड भरवाने जैसे कदम भी उठाए जा सकते हैं।

डीआरडीओ व वायु सेना ने पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली का परीक्षण किया

नई दिल्ली। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) और भारतीय वायु सेना ने ओडिशा के तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन (टीएआरए) हथियार का पहला परीक्षण किया, जो पूरी तरह सफल रहा। टीएआरए एक मॉड्यूलर रेंज एक्सटेंशन किट है, जो भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली है। टीएआरए अनिर्देशित वारहेड को सटीक निर्देशित हथियारों में बदल देती है।

डीआरडीओ के मुताबिक टीएआरए को हैदराबाद के रिसर्च सेंटर इमारत (आरसीआई) और डीआरडीओ की अन्य प्रयोगशालाओं ने डिजाइन और विकसित किया है। जमीन पर मौजूद लक्ष्य को बेअसर

करने के लिए हथियार की मारक क्षमता और सटीकता को बढ़ाने के लिए यह पहला ग्लाइड हथियार है, जिसमें कम लागत वाले सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। इस किट को कई भारतीय उद्योगों के साथ मिलकर बनाया गया है, जिन्होंने पहले ही प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ, वायु सेना, उद्योगों को पहले उड़ान परीक्षण के लिए बधाई दी है और इसे भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण विकास बताया है।

डीआरडीओ के चेयरमैन डॉ. समीर वी कामत ने भी सफल फ्लाइट ट्रायल से जुड़ी टीमों को बधाई दी है।

असम में गिरफ्तार जिहादी के घर पर एनआईए का छापा

बरपेटा (असम)। बरपेटा जिलांतर्गत बरपेटारोड शहर के समीप निसुका में शुक्रवार सुबह राष्ट्रीय जांच एंजेंसी (एनआईए) ने छापेमारी की। मिली जानकारी के अनुसार निसुका गांव निवासी सुल्तान महमूद नामक एक जिहादी के घर पर एनआईए ने छापेमारी की। ज्ञात हो कि, बीते वर्ष 30 दिसंबर को एनआईए ने निसुका गांव निवासी जिहादी को गिरफ्तार किया था। एनआईए इस मामले में अपनी जांच जारी रखते हुए आज जिहादी के घर पर सबूतों को खंगालने के लिए छापेमारी की। एनआईए की टीम ने सुल्तान महमूद के घर पर आज सुबह 5-8 बजे तक तलाशी अभियान चलाया। उल्लेखनीय है कि, सुल्तान महमूद वर्तमान में गुवाहाटी केंद्रीय कारागार में बंद है।

ईडी ने गेमिंग प्लेटफॉर्म गेम्सक्राफ्ट के तीन संस्थापकों को गिरफ्तार किया

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म गेम्सक्राफ्ट के तीन संस्थापकों को शुक्रवार को गिरफ्तार किया। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि ईडी ने दीपक सिंह, पृथ्वीराज सिंह और विकास तनेजा को धनशोधन निवारण अधिनियम 2002 (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत हिरासत में लिया गया है।

दीपक सिंह और पृथ्वीराज सिंह को दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया और उन्हें बेंगलुरु की अदालत में पेश करने के लिए ट्रांजिट रिमांड हासिल की गई है। विकास तनेजा को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया गया है और उन्हें अदालत में पेश किया गया है। ये गिरफ्तारी तब हुई जब केंद्रीय एजेंसी ने कथित धोखाधड़ी और जालसाजी से संबंधित कई प्राथमिकियों का संज्ञान लेते हुए ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म 'गेम्सक्राफ्ट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड' और अन्य संबंधित संस्थाओं के खिलाफ धनशोधन का मामला दर्ज किया।

ईडी ने एक दिन पहले गुरुवार को दिल्ली-एनसीआर और कर्नाटक में 17 स्थानों पर छापेमारी भी की थी और कुछ दस्तावेज जब्त किए थे। ईडी के मुताबिक ये प्लेटफॉर्म 'रमीकल्चर', रमीटाइम ऐप आदि जैसे कई ऑनलाइन 'रियल-मनी गेम्स' का संचालन और स्वामित्व रखता है।

बुलंदशहर में सड़क हादसे में एक ही परिवार के तीन बच्चों समेत पांच लोगों की मौत

बुलंदशहर (उप्र)। बुलंदशहर जिले के कोतवाली देहात क्षेत्र में शुक्रवार को सड़क हादसे में मोटरसाइकिल सवार पति-पत्नी और उनके तीन बच्चों की मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी।

पुलिस के अनुसार हादसे के बाद सभी को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि मृतकों की

पहचान उत्तम कुमार (45), उनकी पत्नी उर्मिला (40) और बच्चे निशान्त (आठ), दिशा (छह) एवं अनायरा (छह) के रूप में हुई है जो धमैडा कीरत गांव के निवासी थे। उन्होंने कहा कि उत्तम कुमार किसी से मोटरसाइकिल लेकर खुर्जा गए थे और लौटते समय रास्ते में यह हादसा हो गया।

एसएसपी के अनुसार, मोटरसाइकिल का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त है। पुलिस का कहना है कि मौके से हरियाणा नंबर की एक ट्रक की नंबर प्लेट मिली है, जिसके आधार पर ट्रक की तलाश की जा रही है। जिले में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है।

सिंह ने बताया कि शवों का पंचनामा भरकर उन्हें पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया है। इससे पहले घटना की सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह एवं अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि ट्रक को जल्द पकड़ लिया जाएगा।

ऑपरेशन सिंदूर ने भारतीय सेना की संयुक्त कार्रवाई और वीरता को दर्शायाः राजनाथ सिंह

नई दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को कहा कि ऑपरेशन सिंदूर देश के हितों की रक्षा के लिए भारतीय सेना की तेज, सटीक और संयुक्त कार्रवाई का सबूत है। साथ ही, उन्होंने सेना से किसी भी सुरक्षा चुनौती से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा। सिंह ने जयपुर में संयुक्त सैन्य कमांडर सम्मेलन में अपने भाषण में यह बात कही।

इस सम्मेलन में बदलते क्षेत्रीय सुरक्षा हालात के मद्देनजर तीनों सेनाओं की युद्ध की तैयारियों की व्यापक समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की बढ़ती क्षमताओं का एक प्रदर्शन था और यह देश के सामूहिक दृढ़संकल्प और नए सैन्य मूल्यों का प्रतीक था। सिंह ने तीनों सेनाओं के कमांडरों से कहा कि वे ऑपरेशन के साथ-साथ मौजूदा वैश्विक सुरक्षा हालात से सीखकर भविष्य के लिए

तैयार रहें। उन्होंने तेजी से बदलते भूराजनीतिक सुरक्षा हालात में तैयार रहने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्वायत्त प्रणालियों, डेटा एनालिटिक्स और सुरक्षित संचार नेटवर्क में क्षमताओं को मजबूत करने की जरूरत पर जोर दिया।

एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, रक्षा मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि भविष्य के संघर्ष हाइब्रिड खतरों, सूचना प्रभुत्व से और साइबर, अंतरिक्ष, विद्युत चुंबकीय तथा संज्ञानात्मक क्षेत्र में एक साथ संचालित किए जाने वाले अभियानों के आधार पर आकार लेंगे।

इसमें कहा गया है कि उभरती प्रौद्योगिकियों के बदलाव लाने वाले असर पर जोर देते हुए, सिंह ने लड़ाई के सभी पहलुओं में देश की एक साथ तैयारी सुनिश्चित करने की अहमियत पर जोर दिया। ऑपरेशन सिंदूर की पहली सालगिरह के एक दिन बाद कॉन्फ्रेंस में सिंह ने यह बात कही। विज्ञप्ति के अनुसार उन्होंने कहा कि भविष्य की लड़ाइयां सिर्फ हथियारों से नहीं, बल्कि नयी सोच और बेहतर तालमेल से जीती जाएंगी। सिंह ने नरेन्द्र मोदी सरकार के अत्याधुनिक हथियारों और प्लेटफॉर्म के जरिए रक्षा बलों की क्षमताओं को बढ़ाने के वादे को भी दोहराया।

दिल्ली-एनसीआर में चढ़ेगा पारा, कई राज्यों में ओलावृष्टि की चेतावनी

नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर के क्षेत्रों में शुक्रवार को आसमान साफ रहा। यहां का अधिकतम तापमान 33-35 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिससे मौसम में कल के मुकाबले आज हल्की गर्मी रही। वहीं, देश के अन्य हिस्सों जैसे मध्य प्रदेश और झारखंड में ओलावृष्टि, जबकि गुजरात में लू चलने का अनुमान है।

भारतीय मौसम विभाग केन्द्र के अनुसार शनिवार को भी मौसम साफ रहने के आसार हैं। यहां का अधिकतम तापमान 35-37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24-26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। हवा का रूख भी दक्षिण-पूर्व दिशा से उत्तर पूर्व दिशा की ओर 10-15 किलोमीटर प्रतिघंटा रहने की संभावना है।

रविवार को भी यही स्थिति रहेगी और अधिकतम तापमान 37-39 जबति न्यूनतम तापमान 25-27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। इसके अलावा, राजधानी में 11 मई को आंशिक रूप से बादल छाए रहने और हल्की वर्षा होने का अनुमान है। इस दौरान, शाम से हवाओं की गति 30-40 किमी प्रति घंटा की रफ्तार तक रहने के आसार हैं। हवा की रफ्तार 50 किमी तक जा सकती है।

संक्षिप्त खबरें

नोएडा में सिर कूचकर दो मालियों की हत्या, निर्माणाधीन हॉस्टल में मिले शव

नोएडा। नोएडा के नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र स्थित एक निर्माणाधीन हॉस्टल के कमरे में शुक्रवार को दो मालियों के शव बरामद हुए। सिर कूचकर दोनों की हत्या की गई हैं। वहीं, मालियों के साथ मौजूद तीसरा साथी गायब है। पुलिस को आशंका है कि उसी ने ही इन दोनों की हत्या करने के बाद फरार हो गया। पुलिस की चार टीमें फरार युवक की तलाश में है। पुलिस उपायुक्त जोन तृतीय डॉक्टर प्रवीन रंजन सिंह ने बताया कि मृतकों की पहचान मेरठ के रहने वाले शीशपाल (42) और दूसरा इंद्र (45) के रुप में की है।उनके साथ मौजूद अभिषेक घटना के बाद से गायब है। तीनों सीताराम इंस्टिट्यूट के पास स्थित एक निर्माणाधीन हॉस्टल में माली का काम कर रहे थे। ये लोग हॉस्टल के अंदर बने कमरे में रहते थे। जांच के दौरान घटनस्थल से जो चीजें बरामद हुई है उससे यह आशंका व्यक्त की जा रही है गुरुवार बीती रात को तीनों ने एक साथ बैठकर खाया-पिया। इसी दौरान किसी बात को लेकर हुए विवाद में अभिषेक ने दोनों की हत्या कर मौके से फरार हो गया। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। डीसीपी ने बताया कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दोनों के सिर पर भारी वस्तु से वार कर उनकी हत्या की गई है। मृतकों के परिजनों को सूचना दे दी है। शवों को पोस्टमार्टम भेजकर घटना के खुलासे के लिए चार टीमें लगाई गई हैं।

संपत्ति विवाद में पिता ने अपने 13 वर्षीय बेटे की हत्या कर शव को तालाब में फेंका, गिरफ्तार

नोएडा। नोएडा के थाना कासना क्षेत्र के सिरसा गांव से लापता हुए एक 13 वर्षीय बच्चे का शव शुक्रवार को एक तालाब में मिला है। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बच्चे के पिता को गिरफ्तार किया है। जांच के दौरान पुलिस को पता चला है कि बच्चों के पिता ने अपने बेटे की हत्या कर अपने परिवार के अन्य लोगों को उसकी हत्या के मामले में बहुत फंसाने के लिए इस घटना को अंजाम दिया था। पुलिस आयुक्त के मीडिया प्रभारी विजय कुमार गुप्ता ने बताया कि सिरसा गांव में रहने वाले मोहित भाटी ने 7 मई को थाना कासना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनका 13 वर्षीय भतीजा सुधांशु उर्फ समर पुत्र प्रदीप 6 मई की रात से घर से लापता है। उन्होंने बताया कि सूचना के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही थी। उन्होंने बताया कि पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज व आसपास के लोगों से जानकारी की तो पता चला कि लड़का अपने पिता के साथ कार में सवार होकर गया था। उन्होंने बताया कि शक होने पर पुलिस ने लड़के के पिता को हिरासत में लेकर गहनता से पूछताछ की तो उसने बताया कि उसने अपने बेटे को ग्राम गुलिस्तानपुर में दोस्त के यहां रखा हुआ है। जब पुलिस वहां गई तो बच्चा नहीं मिला। वह पुलिस को लगातार गुमराह करता रहा। उन्होंने बताया कि आज पुलिस ने लापता बच्चे का शव ग्राम सिरसा के पास बने एक तालाब से बरामद किया है। उन्होंने बताया कि जब बच्चे के पिता से सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने स्वीकार किया कि उसने अपने बेटे की हत्या कर शव को तालाब में फेंक दिया था। प्रॉपर्टी के विवाद में अपने परिवार के अन्य लोगों की फंसाने की नीयत से उसने अपने बेटे की खुद हत्या की थी। उन्होंने बताया कि पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है।

नोएडा में सड़क हादसे में घायल कैंटर चालक की मौत

नोएडा। नोएडा के थाना बीटा- दो क्षेत्र के भाटी गोल चक्कर के पास देर रात को हुए एक सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल कैंटर चालक की शुक्रवार को उपचार के दौरान मौत हो गई है। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस आयुक्त के मीडिया प्रभारी ने बताया कि थाना बीटा- दो क्षेत्र में बीती रात को एक आयशर कैंटर एवं टाटा ट्रेलर के बीच टक्कर हो गई। उन्होंने बताया कि इस घटना में आयशर के चालक वसंत कुमार पुत्र सुरेश चंद मूल निवासी जनपद कासगंज गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उपचार के दौरान शुक्रवार को उनकी मौत हो गई। उन्होंने बताया कि घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उन्होंने बताया कि टाटा ट्रेलर के चालक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इस घटना से आक्रोशित सैकड़ों ड्राइवरों ने भाटी गोल चक्कर के पास एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने उन्हें समझा बुझाकर वापस भेजा।

गौतमबुद्धनगर: गेहूं खरीद में प्रदेश में सातवें नंबर पर पहुंचा जिला

DM मेधा रूपम ने दिए किसानों के त्वरित भुगतान के निर्देश

नोएडा। जनपद गौतमबुद्धनगर में इस वर्ष गेहूं खरीद अभियान तेजी से परवान चढ़ रहा है। जिलाधिकारी मेधा रूपम की अध्यक्षता में एनआईसी (NIC) सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में सामने आया कि जिला गेहूं खरीद की प्रगति के मामले में उत्तर प्रदेश में सातवें स्थान पर और अपने संभाग (मंडल) में प्रथम स्थान पर पहुंच गया है। जिलाधिकारी ने इस उपलब्धि को बनाए रखने और किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश दिए हैं। जिला खाद्य विपणन अधिकारी ने बैठक में जानकारी दी कि इस वर्ष जनपद के लिए 5500 मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अब तक जिला प्रशासन 3162.464 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद कर चुका है, जो कुल लक्ष्य का लगभग 57.50 प्रतिशत है। अब तक कुल 845 किसान इस सरकारी योजना का लाभ उठा चुके हैं। अब तक 716 किसानों के खातों में पीएफएमएस (PFMS) के माध्यम से भुगतान भेजा जा चुका है। शेष किसानों का भुगतान भी निर्धारित समय सीमा में शत-प्रतिशत पूरा किया जाए। खरीदे गए गेहूं को जल्द से जल्द भारतीय खाद्य निगम (FCI) के डिपो तक पहुंचाया जाए। मौसम की अनिश्चितता को देखते हुए गेहूं को त्रिपाल और पॉलिथीन से सुरक्षित ढकने के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। गेहूं के उठान और परिवहन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। संबंधित एजेंसियों के प्रबंधकों को नियमित निरीक्षण के निर्देश दिए गए हैं। समीक्षा बैठक के दौरान प्रशासन के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे, जिनमें अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) अतुल कुमार, अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) प्रियंका, वरिष्ठ कोषाधिकारी शिखा गुप्ता और जिला सहकारिता अधिकारी विवेका सिंह प्रमुख थे। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि क्रय केंद्रों पर आने वाले किसानों के लिए पीने के पानी और छाया जैसी आवश्यक सुविधाओं में कोई कमी न रहे।

सांसद ने किया जनगणना-2027 के प्रथम चरण का शुभारंभ

नोएडा। उत्तर प्रदेश में जनगणना-2027 के ऐतिहासिक अभियान का आगाज हो गया है। नोएडा में इस प्रक्रिया की शुरुआत गौतमबुद्ध नगर के सांसद डॉ. महेश शर्मा ने स्वयं का विवरण दर्ज कर (Self Enumeration) की। इस नई डिजिटल पहल के तहत अब नागरिकों को गणना कर्मियों का इंतजार नहीं करना होगा, बल्कि वे स्वयं ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी जानकारी साझा कर सकेंगे। जनगणना-2027 के अंतर्गत शुरू हुई इस स्वगणना प्रक्रिया के लिए सरकार ने आधिकारिक वेबसाइट sc.census.gov.in जारी की है। नागरिक इस पोर्टल पर जाकर अपनी और अपने परिवार की जनगणना का प्रारूप भर सकते हैं। नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र में इस अभियान को गति देने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। शुभारंभ के अवसर पर सांसद डॉ. महेश शर्मा ने कहा, ₹जनगणना केवल आंकड़ों का संग्रह नहीं है, बल्कि देश की भावी विकास योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने का आधार है। सटीक डेटा से ही सरकार जन-कल्याणकारी नीतियों को सही लाभार्थियों तक पहुँचा पाती है।₹ उन्होंने समस्त नोएडा वासियों से इस डिजिटल अभियान में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। इस अवसर पर नोएडा प्राधिकरण के विशेष कार्याधिकारी इंदु प्रकाश सिंह, प्रभारी सिटी मजिस्ट्रेट अरविंद मिश्रा, प्रबंधक दीपक कुमार एवं सांसद प्रतिनिधि संजय बाली सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

नोएडा हिंसा : उच्चतम न्यायालय का गिरफ्तार छात्रा को जमानत देने से इनकार, उच्च न्यायालय जाने कहा

नोएडा। उच्चतम न्यायालय ने नोएडा में 13 अप्रैल को औद्योगिक श्रमिकों के प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़काने की आरोपी एक छात्रा को शुक्रवार को जमानत देने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने आकृति चौधरी की ओर से पेश वकील से इलाहाबाद उच्च न्यायालय जाने को कहा। पीठ ने टिप्पणी की, ''आप उच्च न्यायालय क्यों नहीं जाते? हर कोई संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत याचिका दायर कर यहां आ जाता है। उच्चतम न्यायालय में 93,000 मामले लंबित हैं।'' चौधरी की ओर से पेश वकील ने उनकी मुवक्किल को जमानत दिए जाने का अनुरोध करते हुए कहा कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तारी के आधार नहीं बताए। उन्होंने शीर्ष अदालत को बताया कि चौधरी दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा है। उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश पुलिस अधिकारियों द्वारा प्रताड़ना का आरोप लगाने वाले केशव आनंद की याचिका पर पुलिस अधिकारियों को भी नोटिस जारी किया। नोएडा की एक अदालत ने इससे पहले औद्योगिक श्रमिकों के प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़काने की आरोपी तीन महिलाओं-चौधरी, मनीषा चौहान और सृष्टि गुप्ता-की सशर्त पुलिस हिरासत की अनुमति दी थी। अदालत ने जांच कार्यवाही के दौरान उनके वकीलों को मौजूद रहने की भी अनुमति दी थी। चौधरी और गुप्ता दोनों दिल्ली की रहने वाली हैं और उनकी उम्र 20 से 30 वर्ष के बीच है। चौधरी ने दौलत राम कॉलेज से इतिहास में परास्नातक किया है जबकि चौहान नोएडा की एक औद्योगिक इकाई में काम करती है। पुलिस ने हिरासत के लिए दायर अर्जी में कहा था, ''आरोपियों के निवास स्थान से महत्वपूर्ण साक्ष्य मिलने की पूरी संभावना है।'' वेतन बढ़ोतरी की मांग कर रहे फैक्टरी श्रमिकों का प्रदर्शन पिछले महीने नोएडा के कुछ हिस्सों में हिंसक हो गया था। अधिकारियों के अनुसार, विभिन्न औद्योगिक इकाइयों के कई श्रमिक वेतन संशोधन की अपनी पुरानी मांग को लेकर एकत्र हुए थे और उन्होंने प्रदर्शन के दौरान नारे लगाए थे।

नोएडा: नवविवाहिता की संदिग्ध मौत

जलती हुई चिता से पुलिस ने शव निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा

नोएडा। नोएडा के थाना दादरी क्षेत्र के गांव घोड़ी बछेड़ा में नव विवाहिता की ससुराल में मौत हो गयी। ससुराल पक्ष के लोग उसका अंतिम संस्कार करने के लिए शमशान घाट ले गए थे। उन्होंने शव को चिता में रखकर आग लगा दी, तभी मौत की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को चिता से उतार कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मृतका के परिजनों की शिकायत पर पति समेत ससुराल पक्ष के पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस उनकी गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है। थाना दादरी के प्रभारी जितेंद्र कुमार सिंह ने शुक्रवार को बताया कि मोनिका का घोड़ी बछेड़ा गांव के रहने वाले अनुज चौहान से तीन माह पूर्व प्रेम विवाह हुआ था। उन्होंने बताया कि देर रात मोनिका का शव पंखे के फंदे से लटका मिला। उसके पति और ससुराल पक्ष के लोगों ने उसके शव को उतार कर आनन-फानन में ले जाकर श्मशान घाट में अंतिम संस्कार करने का प्रयास किया। इन लोगों ने उसके शव को चिता पर रखकर चिता में आग लगा दी थी। इसी बीच सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को चिता से नीचे उतारा। तब तक शव का कुछ अंग आग की चपेट में आ गया था। उन्होंने बताया कि मृतका की मां की शिकायत पर उसके पति समेत ससुराल पक्ष के पांच लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।

डी-पार्क के कार्यों में देरी पर ACEO वंदना त्रिपाठी सख्त

15 सितंबर तक डेडलाइन तय, अधिकारियों से मांगा स्पष्टीकरण

नोएडा। नोएडा प्राधिकरण की अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (ACEO) वंदना त्रिपाठी ने शहर के पार्कों और उद्यान विभाग के विकास कार्यों को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। बोर्ड रूम सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने विकास कार्यों में ढिलाई बरतने वाले अधिकारियों को फटकार लगाई और सेक्टर-62 स्थित डी-पार्क के नवीनीकरण को लेकर अंतिम चेतावनी जारी की। बैठक में सेक्टर-62 स्थित डी-पार्क के सौंदर्यीकरण कार्यों की समीक्षा के दौरान एसीईओ ने देरी पर गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि 15 सितंबर 2026 तक हर हाल में कार्य पूर्ण हो जाना चाहिए। वहीं, सेक्टर-94 स्थित जापानी पार्क के लिए 15 जुलाई 2026 की समय-सीमा तय की गई है, ताकि वृक्षारोपण पूरा कर इसका लोकार्पण किया जा सके। वाइब्रेशन एफएम पार्क के कार्यों में शिथिलता बरतने पर एसीईओ ने कड़ा एक्शन लेते हुए संबंधित उप निदेशक और सहायक निदेशक (उद्यान) से स्पष्टीकरण मांगा है। इसके अलावा: मुख्य द्वार के सौंदर्यीकरण और बाकी बचे कार्यों को युद्ध स्तर पर पूरा करने के निर्देश। प्रस्तावित पार्क का आकलन (Assessment) तीन दिन के भीतर प्रस्तुत करने को कहा गया है। आगामी मानसून को देखते हुए वंदना त्रिपाठी ने पुराने पेड़ों की छंटाई और सूखी शाखाओं को तत्काल हटाने के निर्देश दिए हैं, ताकि तेज हवाओं के दौरान किसी प्रकार की जान-माल की हानि न हो। वहीं, भीषण गर्मी के प्रकोप को देखते हुए श्रमिकों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए काम का समय सुबह 7:30 बजे से निर्धारित कर दिया गया है। एसीईओ ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे आरडब्ल्यूए (RWA) के साथ निरंतर संवाद बनाए रखें ताकि पार्कों से जुड़ी स्थानीय समस्याओं का त्वरित समाधान हो सके।

एनसीआर : बादलों और तेज हवाओं के बीच बढ़ेगा गर्मी का असर, अगले तीन दिनों में 38 डिग्री तक पहुंचेगा पारा

नोएडा। एनसीआर में फिलहाल मौसम का मिजाज लोगों को गर्मी से कुछ राहत दे रहा है। आसमान में बादलों की आवाजाही, बीच-बीच में सूरज की लुका-छुपी और तेज हवाओं के कारण अभी भी भीषण गर्मी का एहसास नहीं हो रहा है। हालांकि भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) के पूर्वानुमान के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान लगातार बढ़ेगा और 10 से 12 मई के बीच अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। मौसम विभाग के स्थानीय पूर्वानुमान के मुताबिक 8 मई को अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। इस दिन आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा और किसी प्रकार की मौसम चेतावनी जारी नहीं की गई है। 9 मई को तापमान बढ़कर 36 डिग्री और न्यूनतम 24 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है। वहीं 10 मई को अधिकतम तापमान 38 डिग्री और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। 11 मई को भी अधिकतम तापमान 38 डिग्री और न्यूनतम 27 डिग्री रहने की संभावना जताई गई है। इस दौरान आसमान आंशिक रूप से बादलों से घिरा रह सकता है। 12 मई को तापमान में हल्की गिरावट के साथ अधिकतम 37 डिग्री और न्यूनतम 27 डिग्री रहने का अनुमान है, जबकि 13 मई को अधिकतम तापमान 36 डिग्री और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। मौसम विभाग ने अगले पांच दिनों तक किसी प्रकार की हीट वेव या अन्य चेतावनी जारी नहीं की है। तेज हवाओं का असर वायु गुणवत्ता पर भी साफ दिखाई दे रहा है। दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद के अधिकांश इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) फिलहाल संतोषजनक और ग्रीन जोन में दर्ज किया गया है। दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में एक्यूआई 53 दर्ज हुआ, जबकि कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और सीआरआरआई मथुरा रोड पर एक्यूआई 78 रहा। अलीपुर में एक्यूआई 94, आया नगर में 91, बुराड़ी क्रॉसिंग में 97 और कैंटोनमेंट क्षेत्र में 96 दर्ज किया गया। हालांकि आनंद विहार में एक्यूआई 122, अशोक विहार में 103 और बवाना में 120 दर्ज होने से वहां हवा की गुणवत्ता मध्यम श्रेणी में रही। नोएडा की बात करें तो सेक्टर-62 में एक्यूआई 79 और सेक्टर-125 में 94 दर्ज किया गया, जो संतोषजनक श्रेणी में है। वहीं सेक्टर-1 में 102 और सेक्टर-116 में 105 दर्ज हुआ। गाजियाबाद के संजय नगर में एक्यूआई 75 और वसुंधरा में 90 दर्ज किया गया, जबकि इंदिरापुरम में 106, लोनी में 142 और गोविंदपुरम में 145 एक्यूआई रिकॉर्ड किया गया। सबसे अधिक खराब स्थिति वेद विहार-लोनी इलाके में रही, जहां एक्यूआई 203 दर्ज हुआ, जो खराब श्रेणी में माना जाता है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि फिलहाल पश्चिमी विक्षोभ और हवाओं की सक्रियता के कारण लोगों को राहत मिल रही है, लेकिन धीरे-धीरे तापमान में बढ़ोतरी होगी और मई के मध्य तक एनसीआर में गर्मी अपना असर दिखाने लगेगी।

मुख्यमंत्री ने राजकीय सर्वोदय विद्यालय का किया औचक निरीक्षण

किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी: सीएम

नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को राजकीय सर्वोदय विद्यालय रूप नगर का औचक निरीक्षण किया। क्लासरूम में विद्यार्थियों से संवाद करते हुए उनसे पेयजल, फायर सेफ्टी, स्वच्छता, गर्मी को लेकर दी जा रही सुविधाओं और शैक्षणिक व्यवस्थाओं की जानकारी ली। मुख्यमंत्री यह जानकारी अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर साझा की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि विद्यार्थियों की सुरक्षा और मूलभूत सुविधाओं में किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने स्कूल प्रशासन से आवश्यक सुधार कार्यों की विस्तृत सूची मांगी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली के सरकारी स्कूल वर्षों से कुव्यवस्था, बदहाल इंफ्रास्ट्रक्चर और मूलभूत सुविधाओं की कमी की मार झेल रहे थे लेकिन पिछले एक साल से हम लगातार स्कूलों में आवश्यक सुविधाएं मजबूत करने, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने और विद्यार्थियों के लिए सुरक्षित एवं बेहतर वातावरण सुनिश्चित करने के लिए युद्धस्तर पर काम कर रहे हैं।

अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश

मंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि विद्यार्थियों की सुरक्षा और मूलभूत सुविधाओं में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने स्कूल प्रशासन से जरूरी सुधार कार्यों की विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी है, ताकि जल्द से जल्द कमियों को दूर किया जा सके।

स्कूलों में सुधार के लिए युद्धस्तर पर कामः गुप्ता

रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली के सरकारी स्कूल लंबे समय से बदहाल इंफ्रास्ट्रक्चर और मूलभूत सुविधाओं की कमी से जूझ रहे थे। हालांकि पिछले एक साल में सरकार लगातार स्कूलों में आवश्यक सुविधाएं मजबूत करने, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने और विद्यार्थियों के लिए सुरक्षित एवं बेहतर माहौल तैयार करने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि हर सरकारी स्कूल में छात्रों को बेहतर शिक्षा के साथ सुरक्षित और सुविधाजनक वातावरण मिले।

दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 11 मई से ग्रीष्मकालीन अवकाश

नौवीं, 10वीं, 12वीं के छात्रों के लिए चलेंगी उपचारात्मक कक्षाएं

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने सरकारी स्कूलों के ग्रीष्मकालीन अवकाश (11 मई से 30 जून तक) का ऐलान किया है। हालांकि इस दौरान कक्षा नौवीं, दसवीं और बारहवीं के विद्यार्थियों के लिए उपचारात्मक कक्षाएं आयोजित की जाएंगी। शिक्षा निदेशालय ने शुक्रवार को अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी सरकारी स्कूलों के प्रधानाध्यापकों को इससे संबंधित परिपत्र जारी किया।

इसमें सभी सरकारी स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि वे कक्षा नौवीं, दसवीं और बारहवीं के विद्यार्थियों के लिए ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान 11 मई से 30 जून तक उपचारात्मक कक्षाएं आयोजित करें, जिनके सत्र 11 मई से 23 मई तक निर्धारित समय सारणी के अनुसार चलेंगे। इसके बाद इन कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए अवकाश घोषित किया गया है। परिपत्र के मुताबिक दोहरी शिफ्ट वाले स्कूलों में उपचारात्मक कक्षाएं अलग-अलग विंग में सोमवार से शनिवार तक संचालित की जाएंगी। कक्षाएं सुबह 7.30 से 10.30 बजे तक संचालित की जाएंगी, हालांकि शिक्षकों को सुबह 7:20 से 11:00 बजे तक किया गया है। प्रत्येक कक्षा की अवधि एक घंटे की होगी। कक्षा 9 और 10 के लिए विज्ञान और गणित पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। हालांकि, विद्यालय प्रमुख (एचओएस) शैक्षणिक आवश्यकताओं, परिणाम विश्लेषण और विषय शिक्षकों की उपलब्धता के आधार पर अन्य विषयों का चयन कर सकते हैं। परिपत्र के मुताबिक कक्षा बारहवीं के लिए छात्रों की शैक्षणिक आवश्यकताओं के अनुसार उपचारात्मक कक्षाओं के विषय विभागाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं।

विद्यालय प्रमुखों को ग्रीष्मकालीन अवकाश शुरू होने से पहले उपचारात्मक कक्षाओं की समय सारिणी तैयार करके संबंधित विभागाध्यक्ष (क्षेत्र) को प्रस्तुत करनी होगा। विद्यार्थियों के लिए उपचारात्मक कक्षाओं के दौरान विद्यालय का ड्रेस पहनना अनिवार्य है और उनकी उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज होगी। उपचारात्मक कक्षाओं में भाग लेने वाले छात्रों के लिए अभिभावक की सहमति (एनओसी) प्राप्त करना आवश्यक है। इस दौरान पुस्तक वितरण के लिए पुस्तकालय सुविधाएं खुली रहेंगी। संबंधित कक्षाओं को पढ़ाने वाले अतिथि/अनुबंध शिक्षकों को उपचारात्मक कक्षाओं के लिए बुलाया जा सकता है। नियमित शिक्षकों की अनुपलब्धता की स्थिति में अतिथि/अनुबंध शिक्षकों को नियुक्त किया जा सकता है।

हर विद्यार्थी की जिंदगी का हिस्सा बने खेल, कॉलेज में नियुक्त हों स्पोर्ट्स कोचः योगेश सिंह

नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के कुलपति प्रो. योगेश सिंह शुक्रवार को वाइस रीगल लॉज स्थित कन्वेंशन हॉल में आयोजित दिल्ली विश्वविद्यालय खेल परिषद (डीयूएससी) के 'वार्षिक खेल पुरस्कार समारोह 2026' में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। समारोह को संबोधित करते हुए कुलपति प्रो. योगेश सिंह ने कहा कि एनईपी-2020 के तहत खेलों को शिक्षा का हिस्सा तो बनाया गया है, लेकिन जरूरत है कि खेल हर विद्यार्थी की ज़िंदगी का भी हिस्सा भी बनें। उन्होंने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय खेल परिषद को भी इस पर काम करना चाहिए और प्रत्येक प्रिंसिपल को अपने कॉलेजों में स्पोर्ट्स कोच नियुक्त करें। कुलपति ने कहा कि खेल हमें जितना सिखाते हैं, हारना सिखाते हैं, गिरना सिखाते हैं और उठना भी सिखाते हैं। इसलिए

खेलों का बहुत महत्व है। जिस चीज के इतने फायदे हों, उसे एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी से कोर सब्जेक्ट में लेकर आएँ, स्पोर्ट्स को कोर में होना चाहिए। प्रो. योगेश सिंह ने कहा कि 21वीं सदी का भारत फेसबुक, इंस्टाग्राम और इंटरनेट का भारत है। जिस देश में इतना ज्यादा स्क्रीन टाइम हो, वहां स्पोर्ट्स को जीवन का हिस्सा बनाना चुनौती तो है, इसलिए रणनीति बनाना जरूरी है। कुलपति ने कहा कि आज के समय में मानसिक स्वास्थ्य एक मुख्य चुनौती बन रहा है। हमारा पूरा शिक्षा तंत्र प्रतिस्पर्धा से जुड़ा है। जब बच्चे इस तंत्र से बाहर सामाजिक और व्यावहारिक जीवन में आते हैं तो उस सहभागिता और सहकार्यता की बात होती है, जो उन्हें शिक्षा में सिखाया ही नहीं गया होता। इसलिए सामूहिक खेलों को बढ़ावा देने की जरूरत है। सामूहिक खेलें सहभागिता का बेहतर उपकरण हैं। समारोह के दौरान कुलपति ने डीयू के उन विद्यार्थियों को पुरस्कारों से सम्मानित किया गया जिन्होंने राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में सराहनीय प्रदर्शन किया है। कार्यक्रम के आरंभ में डीयू खेल परिषद के निदेशक डॉ अनिल कलकल ने परिषद की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में डीयू के प्रदर्शन पर विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की। इस अवसर पर डीन ऑफ कॉलेजेज प्रो. बलराम पाणी, डीयू के दक्षिणी परिसर की निदेशक प्रो. रजनी अब्बी, एसओएल की निदेशक प्रो. पायल मागो और रजिस्ट्रार डॉ विकास गुप्ता सहित अनेकों अधिकारी, प्रिंसिपल, शिक्षक एवं गैर शिक्षक कर्मी तथा हजारों विद्यार्थी उपस्थित रहे।

द्वारका पुलिस का 'ऑपरेशन गैंग बस्ट', 61 बदमाश गिरफ्तार

❖ जनभावना टाइम्स

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस के द्वारका जिले में चलाए गए विशेष अभियान "ऑपरेशन गैंग बस्ट" के तहत पुलिस ने संगठित अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 सक्रिय गैंग का भंडाफोड़ किया है। दो दिन तक चले इस विशेष अभियान में 61 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 2748 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई।यह अभियान दिल्ली पुलिस आयुक्त के निर्देश पर डीसीपी द्वारका कुशल पाल सिंह और अतिरिक्त डीसीपी निहारिका भट्ट की निगरानी में चलाया गया। अभियान में ऑपरेशन यूनिट और विभिन्न थानों की कुल 54 टीमों ने हिस्सा लिया और जिले के संवेदनशील इलाकों में 169 लक्षित रेड की गईं। पुलिस के अनुसार कार्रवाई के दौरान 35 देसी पिस्टल (CMP), 42 जिंदा कारतूस और 3 चाकू बरामद किए गए। इसके अलावा 5909 शराब की क्वार्टर बोतलें, अपराध में इस्तेमाल 3 दोपहिया वाहन और 93 संदिग्ध वाहन भी जब्त किए गए। अभियान के दौरान पुलिस ने विक्की टक्कर गैंग, धारे गैंग, शक्ति शारदा गैंग, सद्दाम गौरी गैंग, काला झटेड़ी गैंग, मंजीत महाल गैंग और हेमंत गैंग के सदस्यों को गिरफ्तार किया। इनमें कई शूटर और फाइनेंसर शामिल हैं। सद्दाम गौरी गैंग से नकदी, मोबाइल फोन और सट्टा सामग्री भी बरामद की गई। वहीं काला झटेड़ी गैंग के पास से सेमी-ऑटोमैटिक पिस्टल बरामद हुई। इस विशेष ड्राइव के दौरान विभिन्न धाराओं में कुल 53 आपराधिक मामले दर्ज किए गए।

पुलिस ने एक्साइज एक्ट, आर्म्स एक्ट, जुआ अधिनियम और अन्य निवारक धाराओं के तहत कार्रवाई की। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि द्वारका जिले में अपराध और गैंग गतिविधियों के खिलाफ आगे भी लगातार अभियान जारी रहेगा। पुलिस ने लोगों से संदिग्ध गतिविधियों की सूचना साझा करने की अपील भी की है।

दिल्ली की उपमहापौर ने किया रामनगर वार्ड का निरीक्षण

नई दिल्ली। दिल्ली की उपमहापौर डॉ. मोनिका पंत ने शुक्रवार को शाहदरा उत्तरी क्षेत्र में रामनगर वार्ड संख्या 222 का क्षेत्रीय निरीक्षण किया। उपमहापौर ने क्षेत्र में सफाई व्यवस्था का जायजा लिया तथा संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्वच्छता व्यवस्था को और अधिक प्रभावी, नियमित एवं सुदृढ़ बनाया जाए, जिससे क्षेत्रवासियों को स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण उपलब्ध हो सके। उन्होंने विशेष रूप से सार्वजनिक स्थलों एवं आसपास के क्षेत्रों में नियमित सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मोनिका पंत ने निगम विद्यालय का भी निरीक्षण किया तथा विद्यालय परिसर में उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं, स्वच्छता व्यवस्था एवं विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि विद्यालयों में

स्वच्छता, पेयजल, शौचालय एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं का समुचित रखरखाव सुनिश्चित किया जाए, ताकि विद्यार्थियों को बेहतर एवं अनुकूल शैक्षणिक वातावरण प्राप्त हो सके। उपमहापौर ने कहा कि दिल्ली नगर निगम नागरिकों को बेहतर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा स्वच्छ एवं व्यवस्थित वातावरण सुनिश्चित करने के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। उन्होंने अधिकारियों को क्षेत्रीय समस्याओं के त्वरित समाधान एवं विकास कार्यों में गति बनाए रखने के निर्देश दिए। इस अवसर पर क्षेत्रीय निगम पार्षद चंद्र प्रकाश शर्मा तथा शाहदरा उत्तरी क्षेत्र की उपायुक्त ममता यादव सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने छात्रों के लिए आयोजित किया मेगा रोड सेफ्टी जागरूकता कार्यक्रम

❖ जनभावना टाइम्स

नई दिल्ली। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने पीआरओ दिल्ली पुलिस और शिक्षा निदेशालय, जीएनसीटीडी के सहयोग से शुक्रवार को दिल्ली पुलिस मुख्यालय स्थित आदर्श ऑडिटोरियम में मेगा रोड सेफ्टी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम का उद्देश्य स्कूली छात्रों में सड़क सुरक्षा और जिम्मेदार यातायात व्यवहार के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की रोड सेफ्टी सेल द्वारा किया गया। इसे यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम भी किया गया, जिससे दिल्ली के विभिन्न स्कूलों के करीब एक लाख छात्रों ने वर्चुअली हिस्सा लिया। वहीं करीब 400 छात्र कार्यक्रम स्थल पर मौजूद रहे।इस दौरान दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों और विशेषज्ञों ने सड़क सुरक्षा से जुड़े विभिन्न विषयों पर प्रस्तुति दी और इंटरैक्टिव सत्र आयोजित किए। छात्रों को ट्रैफिक नियमों के पालन, सड़क अनुशासन, पैदल यात्रियों और साइकिल चालकों की सुरक्षा, हेलमेट और सीट बेल्ट के सही उपयोग, ओवरस्पीडिंग और मोबाइल फोन इस्तेमाल कर वाहन चलाने के खतरों के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही सड़क दुर्घटना के दौरान अपनाए जाने वाले प्राथमिक सुरक्षा उपायों और इमरजेंसी रिस्पॉन्स के बारे में भी जागरूक किया गया।कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए शैक्षणिक फिल्में और ऑडियो-विजुअल प्रस्तुतियां भी दिखाई गईं। छात्रों ने कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक भाग लिया और सड़क सुरक्षा संबंधी जानकारियों में गहरी रुचि दिखाई।दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। अधिकारियों ने बताया कि बच्चों में शुरुआती स्तर से ही सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता विकसित करना इस पहल का मुख्य उद्देश्य है, ताकि वे भविष्य में जिम्मेदार नागरिक और सुरक्षित सड़क उपयोगकर्ता बन सकें। इसके अलावा दिल्ली ट्रैफिक पुलिस 18 मई से 5 जून 2026 तक सभी चार ट्रैफिक ट्रेनिंग पार्कों में समर कैंप भी आयोजित करेगी। तीन चरणों में आयोजित होने वाले इस कैंप में सड़क सुरक्षा, ट्रैफिक नियम, सेल्फ डिफेंस, साइबर सुरक्षा, फर्स्ट एड, सीपीआर, जेंडर सेंसिटाइजेशन समेत कई जागरूकता और शैक्षणिक गतिविधियां कराई जाएंगी। साथ ही विभिन्न प्रतियोगिताओं और इंटरैक्टिव सत्रों का आयोजन भी किया जाएगा। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त ट्रैफिक जोन-1 विजयांता गोयल आर्य ने कहा कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान, सामुदायिक भागीदारी और ट्रैफिक नियमों के सख्त पालन के जरिए राजधानी की सड़कों को सुरक्षित बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है।

दिल्ली में सड़क प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम शुरू

पर्यावरण मंत्री सिरसा बोले- स्वच्छ हवा की लड़ाई सड़क पर जीतनी होगी

नई दिल्ली। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) ने शुक्रवार को सड़क प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया। यह दिल्ली में फैले हुए वायु प्रदूषण स्रोतों की जमीनी निगरानी और तेज समाधान सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस कार्यक्रम के तहत हर जिले में विशेष फील्ड सर्वेयर तैनात किए गए हैं, जो हर कार्य दिवस पर निगरानी अधिकारियों की देखरेख में दिल्ली की सड़कों का व्यवस्थित सर्वे करेंगे और रियल-टाइम में प्रदूषण हॉट स्पॉट की पहचान करेंगे।

पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने शुक्रवार को एक विज्ञप्ति जारी कर कहा कि दिल्ली की स्वच्छ हवा की लड़ाई जमीन पर, गली-गली और सड़क पर जीतनी होगी। रोड राडार के माध्यम से सरकार रोजाना निगरानी, रियल-टाइम रिपोर्टिंग और सीधे विभागीय

जवाबदेही की वैज्ञानिक व्यवस्था लागू कर रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के मार्गदर्शन में दिल्ली सरकार स्वच्छ हवा के बड़े मिशन पर काम कर रही है। इसमें वैज्ञानिक तरीकों, मजबूत मॉनिटरिंग, तेज रिस्पॉन्स सिस्टम और जमीनी स्तर पर प्रभावी अनुपालन शामिल है। यह प्रोग्राम उसी व्यापक रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मंत्री ने बताया कि नई व्यवस्था के तहत हर जिले के 13 सर्वेयर मिलकर दिल्ली की लगभग 18,000 किमी सड़कों को कवर करेंगे। इसमें एमसीडी, नई दिल्ली नगर परिषद, लोक निर्माण विभाग और दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड के सभी क्षेत्र शामिल होंगे। हर महीने दिल्ली के पूरे सड़क नेटवर्क का सर्वे किया जाएगा। प्रत्येक सर्वेयर को रोजाना कम से कम 20 किमी सड़क का सर्वे करने की जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने बताया कि एमसीडी -311 मोबाइल ऐप के माध्यम से हर सर्वेयर जियो-टैग्ड फील्ड सर्वे करेगा और रोजाना कम से कम 70 फोटो आधारित प्रदूषण संबंधी शिकायतें दर्ज करेगा। इस प्रकार पूरे शहर में प्रतिदिन लगभग 1,000 मुद्दों की पहचान होगी, जिससे संबंधित विभागों को लगातार जमीनी जानकारी मिलती रहेगी। सिस्टम में ऐसी व्यवस्था भी की गई है जिससे एक ही समस्या की दोबारा शिकायत दर्ज न हो और हर शिकायत एक अलग एवं कार्रवाई योग्य प्रदूषण स्रोत से जुड़ी हो। यह प्रोग्राम वायु प्रदूषण से जुड़े 11 प्रकार के कारणों की निगरानी करेगा। इनमें कच्ची सड़कें, टूटे फुटपाथ, डिवाइडर और गड्ढों से उड़ने वाली धूल, सड़क किनारे रेत या निर्माण सामग्री, बिना पक्के और अव्यवस्थित पार्किंग स्थल, कचरा एवं ओवरफ्लो होते ढलाव, सड़क किनारे बायोमास और कचरा जलाना, प्लास्टिक जलाना, निर्माण एवं ध्वस्तीकरण का मलबा, हरियाली की आवश्यकता वाले सड़क किनारे क्षेत्र, सेंट्रल वर्ज पर हरियाली की कमी, निर्माण स्थलों से उड़ने वाली धूल तथा सर्वे के दौरान पहचाने गए अन्य प्रदूषण स्रोत शामिल हैं।

विकास कार्यों का शुभारंभ कर बोले मंत्री कपिल मिश्रा, जल्द शुरू होगी यमुना में क्रूज सेवा

नई दिल्ली। दिल्ली के कला, संस्कृति एवं भाषा मंत्री कपिल मिश्रा ने शुक्रवार को करावल नगर विधानसभा के सोनिया विहार में मुख्यमंत्री विकास निधि से तीसरा पुस्ता मार्केट के सड़क एवं नालों के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। इस दौरान मंत्री ने तैयार लिंक गलियों का लोकार्पण भी किया। उन्होंने कहा कि यमुना में क्रूज चलाने की योजना पर काम चल रहा है और 1 से 2 महीने में इसे शुरू किया जाएगा। इस अवसर पर निगम पार्षद सोनी अनुपम पांडे भी उपस्थित रहीं। कपिल मिश्रा ने यहां लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले एक साल से अब तक करावल नगर में 300 करोड़ रुपये से ज्यादा के विकास कार्य स्वीकृत हो चुके हैं। लगभग 70 करोड़ रुपये की लागत से सीवर का जाल बिछाने का कार्य अकेले सोनिया विहार में हो रहा है और सभापुर वार्ड में भी सीवर का काम एक महीने में शुरू हो जाएगा। मंत्री ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों में विधायक एवं पार्षदों के पास विकास कार्यों के लिए हमेशा फंड की कमी रहती थी, इससे निगम पार्षदों और विधायकों में तनाव की स्थिति बनी रहती थी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यह निर्णय लिया कि निगम पार्षदों के हाथ भी मजबूत किए जाएंगे और एक-एक करोड़ रुपये का फंड सभी निगम पार्षदों को दिया गया है।

संपादकीय

बदली बंगाल की सियासत

विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद पश्चिम बंगाल की राजनैतिक और सामाजिक तस्वीर में ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिल रहा है। डेढ़ दशक के ममता बनर्जी के शासन के बाद, राज्य में अब भाजपा के नेतृत्व में एक नए युग की शुरूआत मानी जा सकती है। ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ असंतोष, भ्रष्टाचार व शासन संबंधी सवाल, हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण और मतदाता सूची पुनरीक्षण विवाद को इस बड़े राजनीतिक बदलाव का प्रमुख कारण माना जा सकता है। गौरतलब है कि ताजा विधान सभा चुनाव नतीजों ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में ऐसे दौर का अंत कर दिया, जिसकी शुरूआत 2011 में ममता बनर्जी के 'परिवर्तन' के नारे के साथ हुई थी। 15 साल तक सत्ता में रहने के बाद तृणमूल कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई और भाजपा ने निर्णायक बहुमत हासिल कर लिया। इसे महज सरकार बदलने का नतीजा नहीं माना जा सकता, बल्कि यह परिवर्तन बंगाल की सामाजिक संरचना, प्रशासनिक असंतोष व राष्ट्रीय राजनीति के बदलते संतुलन का मिला-जुला संकेत है। भाजपा की इस जीत का फलक जितना व्यापक है, लेकिन इसकी पटकथा सरल, सीधी रेखा में नहीं पढ़ी जा सकती। यह चुनावी परिणाम जितना तृणमूल कांग्रेस के क्षरण का कारण है, उतना ही भाजपा के संगठनात्मक विस्तार, मतदाता पुनर्संरचना और राजनैतिक ध्रुवीकरण का भी नतीजा है।पश्चिम बंगाल के बदले राजनैतिक परिपेक्ष को समझने के लिए हमें अतीत में जाना पड़ेगा। 2011 में तृणमूल कांग्रेस ने वामपंथी शासन को 34 वर्ष बाद सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया था। तत्कालीन वाम नेतृत्व पर आरोप था कि उसने जनता के भीतर बढ़ रहे असंतोष को समय रहते समझा नहीं। 2026 में ममता सरकार भी इन्हीं आरोपों की चपेट में आई। तृणमूल नेतृत्व में बढ़ता भ्रष्टाचार और बेरोज़गारी, नागरिक असंतोष और पार्टी कार्यकर्ताओं के बढ़ते आतंक और स्थानीय सिंडीकेट का दबदबा तृणमूल कांग्रेस के पतन की मुख्य वजह बनी। इसके अलावा भाजपा को एक चुनौती के बजाए बाहरी राजनैतिक प्रतिद्वंद्वी मानने की रणनीति भी तृणमूल कांग्रेस के लिए महंगी साबित हुई। ममता बनर्जी की एक राजनैतिक चूक पर भी यहां गौर फरमाना जरूरी है। 2024 लोकसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने 42 में से 29 सीटें जीत कर भले ही अपनी ताकत दिखाई हो लेकिन अगले दो वर्षों में कई आंतरिक घटनाओं ने पश्चिम बंगाल का राजनैतिक माहौल जिस तरह से बदला, उसकी ममता बनर्जी लगातार अनदेखी करती रहीं। इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को हुआ। बीते विधानसभा चुनाव में मतादाताओं ने पार्टी को बंपर वोट दिया। इसका नतीजा रहा कि भाजपा दो सौ से अधिक सीटें जीतने में कामयाब रही।

पढ़ाई तो बढ़ी... लेकिन स्किल क्यों नहीं ?

हमारी शिक्षा प्रणाली लंबे समय से रटने की संस्कृति पर टिकी रही है। बच्चों को यह सिखाया जाता है कि कौन-सा प्रश्न कैसे आएगा और उसका उत्तर किस तरह लिखना है। इस प्रक्रिया में उनकी जिज्ञासा धीरे-धीरे खत्म हो जाती है। वे सवाल पूछने से कतराने लगते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं वे "गलत" न साबित हो जाएँ। रचनात्मकता और स्वतंत्र सोच, जो किसी भी समाज के विकास के लिए जरूरी होती है, इस दबाव में दब जाती है। जब यही बच्चे उच्च शिक्षा पूरी कर नौकरी की दुनिया में प्रवेश करते हैं, तब वास्तविकता सामने आती है। कंपनियाँ केवल डिग्री नहीं, बल्कि कौशल चाहती हैं— समस्या को समझने की क्षमता, टीम के साथ काम करने का हुनर, संवाद कौशल, और परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने की योग्यता। लेकिन शिक्षा व्यवस्था ने उन्हें इन सबके लिए तैयार ही नहीं किया होता। यही कारण है कि डिग्री बढ़ने के बावजूद रोजगार के अवसरों का लाभ उठाने में युवा पीछे रह जाते हैं। यह केवल बेरोजगारी का नहीं, बल्कि "स्किल गैप" का संकट है।

- डॉ. सत्यवान सौरभ

आज का समाज एक अजीब विरोधाभास के दौर से गुजर रहा है। एक तरफ शिक्षा का स्तर पहले से कहीं अधिक ऊँचा दिखाई देता है—हर घर में बच्चे पढ़ रहे हैं, कोचिंग, ऑनलाइन क्लासेस और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे हैं, और परिणामस्वरूप अंक भी लगातार बेहतर हो रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक सवाल लगातार सिर उठाता है—क्या सच में हम सीख रहे हैं, या सिर्फ अंकों का संग्रह कर रहे हैं?

यह विडंबना केवल व्यक्तिगत स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे शिक्षा तंत्र की दिशा पर प्रश्नचिह्न खड़ा करती है। स्कूल से लेकर कॉलेज तक बच्चों को एक ऐसी दौड़ में शामिल कर दिया गया है, जहाँ लक्ष्य केवल अच्छे अंक लाना, उच्च रैंक हासिल करना और अधिक से अधिक प्रमाणपत्र जुटाना रह गया है। इस पूरी प्रक्रिया में "सीखना" कहीं पीछे छूट गया है। बच्चे यह समझने लगते हैं कि सफलता का मतलब है परीक्षा में सही उत्तर लिख देना, न कि उस ज्ञान को जीवन में लागू कर पाना। इसी कारण आज हम ऐसे युवाओं को देखते हैं जो कागज पर बेहद सफल हैं, लेकिन वास्तविक जीवन की चुनौतियों के सामने असहज हो जाते हैं। वे जटिल प्रश्न हल कर सकते हैं, लेकिन सरल समस्याओं के व्यावहारिक समाधान में अटक जाते हैं। आत्मविश्वास की कमी, निर्णय लेने में झिझक, और नई परिस्थितियों में खुद को ढालने की कमजोरी—ये सब उस शिक्षा का परिणाम हैं जो "याद करने" पर अधिक और "समझने" पर कम आधारित है।

हमारी शिक्षा प्रणाली लंबे समय से रटने की संस्कृति पर टिकी रही है। बच्चों को यह सिखाया जाता है कि कौन-सा प्रश्न कैसे आएगा और उसका उत्तर किस तरह लिखना है। इस प्रक्रिया में उनकी जिज्ञासा धीरे-धीरे खत्म हो जाती है। वे सवाल पूछने से कतराने लगते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं वे "गलत" न साबित हो जाएँ। रचनात्मकता और स्वतंत्र सोच, जो किसी भी समाज के विकास के लिए जरूरी होती है, इस दबाव में दब जाती है। जब यही बच्चे उच्च शिक्षा पूरी कर नौकरी की दुनिया में प्रवेश करते हैं, तब वास्तविकता सामने आती है। कंपनियाँ केवल डिग्री नहीं, बल्कि कौशल चाहती हैं—समस्या को समझने की क्षमता, टीम के साथ काम करने का हुनर, संवाद कौशल, और परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने की योग्यता। लेकिन शिक्षा व्यवस्था ने उन्हें इन सबके लिए तैयार ही नहीं किया होता। यही कारण है कि डिग्री बढ़ने के बावजूद रोजगार के अवसरों का लाभ उठाने में युवा पीछे रह जाते हैं। यह केवल बेरोजगारी का नहीं, बल्कि "स्किल गैप" का संकट है।

इस पूरी प्रक्रिया का एक और गंभीर पहलू है—मानसिक दबाव। आज के छात्र पर अपेक्षाओं का बोझ बहुत अधिक है। परिवार, समाज और प्रतिस्पर्धा—तीनों मिलकर उस पर निरंतर दबाव बनाते हैं कि वह हर हाल में अच्छा प्रदर्शन करे। लेकिन जब पढ़ाई का उद्देश्य स्पष्ट नहीं होता, तो यह दबाव धीरे-धीरे तनाव और भ्रम में बदल जाता है। बच्चे यह समझ ही नहीं पाते कि वे जो पढ़ रहे हैं, उसका उनके जीवन से क्या संबंध है।

असल में शिक्षा का उद्देश्य कभी केवल परीक्षा पास करना नहीं था। शिक्षा का अर्थ है व्यक्ति को जीवन के लिए तैयार करना—उसे सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता देना। यह उसे केवल जानकारी नहीं, बल्कि उस जानकारी का उपयोग करना सिखाती है। लेकिन जब शिक्षा केवल अंकों तक सीमित हो जाती है, तो वह अपने मूल उद्देश्य से भटक जाती है। समस्या का समाधान भी इसी समझ में छिपा है। जब तक हम शिक्षा को केवल "परिणाम" के रूप में देखेंगे, तब तक यह समस्या बनी रहेगी। जरूरत है कि हम प्रक्रिया पर ध्यान दें—कैसे बच्चे सीख रहे हैं, क्या वे वास्तव में समझ रहे हैं, क्या वे अपने ज्ञान को लागू कर पा रहे हैं। पाठ्यक्रम को ऐसा बनाया जाना चाहिए जो बच्चों को सोचने और प्रयोग करने के लिए प्रेरित करे। परीक्षा प्रणाली को इस तरह बदला जाना चाहिए कि वह केवल याददाश्त नहीं, बल्कि समझ और अनुप्रयोग को परखे।

शिक्षकों की भूमिका भी इस बदलाव में बेहद महत्वपूर्ण है। उन्हें केवल पाठ पढ़ाने वाले नहीं, बल्कि मार्गदर्शक बनना होगा, जो बच्चों को सवाल पूछने, गलती करने और उससे सीखने के लिए प्रेरित करें। वहीं अभिभावकों को भी अपनी सोच बदलनी होगी। बच्चों की सफलता को केवल अंकों से नहीं, बल्कि उनके कौशल, आत्मविश्वास और समझ से आंकना होगा। डिजिटल युग ने सीखने के नए रास्ते खोले हैं, लेकिन इनका सही उपयोग तभी संभव है जब हमारे पास सीखने की सही दृष्टि हो। केवल जानकारी तक पहुँच होना पर्याप्त नहीं है, उसे समझना और उपयोग करना ही असली शिक्षा है। अंततः यही बात सबसे महत्वपूर्ण है कि नंबर यह बताते हैं कि आपने कितना याद किया, लेकिन ज्ञान और कौशल यह बताते हैं कि आप क्या कर सकते हैं। यदि हमारी शिक्षा प्रणाली इस अंतर को समझने में सफल हो जाती है, तो न केवल छात्रों का भविष्य बेहतर होगा, बल्कि समाज भी अधिक सक्षम और जागरूक बनेगा। आज जरूरत है इस सवाल को गंभीरता से पूछने की—क्या हम सच में शिक्षित हो रहे हैं, या सिर्फ शिक्षित दिखने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि जब तक इस सवाल का ईमानदार जवाब नहीं मिलेगा, तब तक पढ़ाई बढ़ती रहेगी, लेकिन स्किल नहीं बढ़ेगी।

तमिलनाडु: हिंदू बहुसंख्यक राज्य में भी द्रविड़ राजनीति क्यों पड़ती है भारी?

- डॉ. प्रियंका सौरभ

भारत की राजनीति को अक्सर सरल समीकरण में समझने की कोशिश की जाती है- जहाँ हिंदू आबादी अधिक होगी, वहाँ भारतीय जनता पार्टी स्वतः मजबूत होगी। लेकिन तमिलनाडु इस धारणा को चुनौती देता है। तमिलनाडु में हिंदू आबादी लगभग 85 प्रतिशत से अधिक है। राज्य मंदिरों, परंपराओं और धार्मिक आस्थाओं के लिए प्रसिद्ध है, फिर भी भाजपा यहाँ अब तक वैसी राजनीतिक सफलता हासिल नहीं कर पाई जो उसे उत्तर और पश्चिम भारत के कई राज्यों में मिली। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों है? क्या तमिलनाडु की राजनीति धर्म से अलग किसी और आधार पर चलती है? या भाजपा राज्य की सामाजिक और सांस्कृतिक मानसिकता को अब तक पूरी तरह समझ नहीं पाई?

तमिलनाडु को समझने के लिए सबसे पहले उसके राजनीतिक इतिहास को समझना जरूरी है। यह राज्य केवल चुनावी राजनीति से नहीं बल्कि एक बड़े सामाजिक आंदोलन से प्रभावित रहा है। बीसवीं सदी में ई. वी. रामासामी यानी पेरियार के नेतृत्व में द्रविड़ आंदोलन शुरू हुआ। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य ब्राह्मणवादी वर्चस्व, जातिगत ऊँच-नीच और उत्तर भारतीय प्रभुत्व का विरोध था। पेरियार ने तर्कवाद, सामाजिक न्याय और क्षेत्रीय अस्मिता को राजनीति का केंद्र बनाया। बाद में इसी विचारधारा से डीएमके और एआईएडीएमके जैसी शक्तिशाली पार्टियाँ उभरीं। यही वह बिंदु है जहाँ तमिलनाडु की राजनीति बाकी भारत से अलग हो जाती है। उत्तर भारत में जहाँ धार्मिक पहचान अक्सर चुनावी राजनीति का बड़ा आधार बनती है, वहीं तमिलनाडु में "तमिल पहचान" अधिक महत्वपूर्ण रही। यहाँ भाषा, संस्कृति और क्षेत्रीय गर्व को राजनीति के केंद्र में रखा गया। लोगों के भीतर यह भावना गहरी रही कि दिल्ली की राजनीति तमिल समाज की विशिष्टता को पूरी तरह नहीं समझती। भाजपा को कई बार इसी कारण उत्तर भारतीय पार्टी के रूप में देखा गया।

तमिलनाडु में हिंदी विरोध का इतिहास भी भाजपा के लिए बड़ी चुनौती बना। 1960 के दशक में जब हिंदी को राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने की कोशिश हुई, तब तमिलनाडु में बड़े आंदोलन हुए। लोगों को लगा कि उनकी भाषा और संस्कृति पर खतरा है। यही आंदोलन द्रविड़ दलों को मजबूत बनाने का कारण बना। आज भी तमिल पहचान और भाषा का मुद्दा यहाँ बेहद संवेदनशील है। भाजपा भले हिंदी थोपने से इनकार करे लेकिन उसके राष्ट्रीय विमर्श को कई लोग हिंदी और उत्तर भारतीय संस्कृति के प्रभाव से जोड़कर देखते हैं। यह कहना गलत होगा कि तमिलनाडु में हिंदू धर्म का प्रभाव नहीं है। राज्य में प्रसिद्ध मंदिरों की लंबी परंपरा है- मीनाक्षी अम्मन मंदिर, रामनाथस्वामी मंदिर और बृहदीश्वर मंदिर जैसे धार्मिक स्थल केवल पूजा के केंद्र नहीं बल्कि तमिल संस्कृति और गौरव का हिस्सा भी हैं। लेकिन तमिलनाडु में धार्मिक आस्था का अर्थ हमेशा राजनीतिक हिंदुत्व नहीं रहा। यहाँ लोग मंदिरों में गहरी श्रद्धा रखते हैं लेकिन वोट देते समय क्षेत्रीय हित, सामाजिक न्याय और स्थानीय नेतृत्व को प्राथमिकता देते हैं।

भाजपा की सबसे बड़ी चुनौती यह रही कि वह लंबे समय तक तमिलनाडु में मजबूत स्थानीय नेतृत्व तैयार नहीं कर पाई। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ, गुजरात में नरेन्द्र मोदी और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान समय-समय पर भाजपा की क्षेत्रीय ताकत का चेहरा बने। लेकिन तमिलनाडु में दशकों तक पार्टी के पास ऐसा कोई जनाधार वाला नेता नहीं था जो आम तमिल मतदाता से भावनात्मक जुड़ाव बना सके। हाल के वर्षों में के. अन्नामलाई ने भाजपा को नई ऊर्जा दी है लेकिन अभी भी पार्टी का संगठन राज्य के ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में उतना मजबूत नहीं जितना द्रविड़ दलों का है।

तमिलनाडु की राजनीति में सामाजिक न्याय और आरक्षण का मुद्दा बेहद महत्वपूर्ण है। द्रविड़ आंदोलन ने पिछड़े वर्गों और गैर-ब्राह्मण समुदायों को राजनीतिक शक्ति दी। यही कारण है कि राज्य में सामाजिक न्याय की राजनीति बहुत गहराई से स्थापित हो चुकी है। भाजपा की छवि लंबे समय तक अलग रही है। हालांकि भाजपा ने अब पिछड़े वर्गों और दलित समुदायों तक पहुँच बढ़ाने की कोशिश की है लेकिन तमिलनाडु में द्रविड़ दलों की सामाजिक पकड़ अब भी ज्यादा मजबूत है।

इसके अलावा तमिलनाडु में कल्याणकारी राजनीति का मॉडल भी दूसरे दलों के लिए चुनौतीपूर्ण है। मुफ्त राशन, महिला सहायता योजनाएँ, छात्रवृत्तियाँ, स्वास्थ्य सेवाएँ और सब्सिडी जैसी योजनाओं ने द्रविड़ दलों को जनता से गहराई से जोड़ रखा। यहाँ मतदाता केवल वैचारिक मुद्दों पर नहीं, बल्कि रोजमर्रा की सुविधाओं और राज्य सरकार की योजनाओं के आधार पर भी वोट करते हैं। भाजपा का राष्ट्रीय विकास मॉडल लोगों को आकर्षित करता है लेकिन तमिलनाडु में स्थानीय कल्याणकारी राजनीति की पकड़ बहुत मजबूत है। एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि तमिलनाडु में राजनीति का भावनात्मक केंद्र "क्षेत्रीय स्वाभिमान" रहा है। यहाँ लोग खुद को पहले तमिल मानते हैं- हालाँकि इसका अर्थ अलगाववाद नहीं बल्कि सांस्कृतिक गर्व है। भाजपा का राष्ट्रवादी विमर्श कई बार इस क्षेत्रीय अस्मिता से टकराता दिखाई देता है। द्रविड़ दल इस भावना को लगातार मजबूत करते रहे हैं कि वे "तमिल हितों" के असली रक्षक हैं। यह भी सच है कि भाजपा पूरी तरह कमजोर नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में उसका वोट प्रतिशत बढ़ा है। शहरी क्षेत्रों, शिक्षित युवाओं और कुछ मध्यमवर्गीय समूहों में पार्टी ने अपनी उपस्थिति मजबूत की है। सोशल मीडिया और राष्ट्रवादी मुद्दों के माध्यम से भाजपा ने राज्य में नई राजनीतिक जगह बनाने की कोशिश की है। लेकिन वोट प्रतिशत बढ़ना और सत्ता तक पहुँचना दोनों अलग बातें हैं। तमिलनाडु में द्रविड़ दलों का संगठनात्मक नेटवर्क, बूथ स्तर की पकड़ और दशकों पुरानी राजनीतिक संस्कृति भाजपा के लिए बड़ी बाधा बनी हुई है।

इसके साथ ही गठबंधन की राजनीति भी एक महत्वपूर्ण कारण है। तमिलनाडु में चुनाव अक्सर बड़े गठबंधनों के आधार पर लड़े जाते हैं। द्रविड़ दलों ने समय-समय पर राष्ट्रीय पार्टियों को अपने साथ जोड़कर चुनावी समीकरण मजबूत किए। भाजपा कभी एआईएडीएमके के साथ रही लेकिन यह गठबंधन उसे व्यापक जनसमर्थन में तब्दील नहीं करा पाया। कई मतदाता भाजपा को सहयोगी पार्टी के रूप में स्वीकार करते हैं लेकिन मुख्य शक्ति के रूप में नहीं। तमिलनाडु की राजनीति यह भी दिखाती है कि भारत केवल धार्मिक पहचान से नहीं चलता। यहाँ भाषा, संस्कृति, जातीय संरचना, सामाजिक न्याय और क्षेत्रीय भावनाएँ मिलकर राजनीति को आकार देती हैं। यही कारण है कि हिंदू बहुसंख्यक होने के बावजूद राज्य में भाजपा को वैसी सफलता नहीं मिली जैसी उत्तर भारत के कई राज्यों में मिली। दरअसल, तमिलनाडु भारतीय लोकतंत्र का अलग अध्याय है। यहाँ मंदिर भी हैं, आस्था भी है, धार्मिक परंपराएँ भी हैं लेकिन राजनीति का केंद्र केवल धर्म नहीं है।

वैदिक सूक्तों के द्रष्टा स्मृतिकार महर्षि पराशर

धर्मकर्म

वैदिक सूक्तों के द्रष्टा और ग्रंथकार के रूप में प्रसिद्ध गोत्रप्रवर्तक ऋषि पराशर शक्ति मुनि के पुत्र एवं ब्रह्मर्षि वशिष्ठस के पौत्र थे। इनकी माता का नाम अदृश्यरन्ति था, जो उतथ्यि मुनि की पुत्री थी। कहीं-कहीं इन्हें पाराशर भी कहा गया है। पौराणिक मान्यतानुसार पराशर प्राचीन भारतीय ऋषि मुनि परंपरा की श्रेणी में एक महान ऋषि महर्षि पराशर का जन्म अपने पिता शक्ति की मृत्यूश के बाद हुआ था, तथापि गर्भावस्थाक में ही इन्हों ने पिता द्वारा कही हुई वेद ऋचायें कंठस्थप कर ली थी। प्रमुख योग सिद्यिों के द्वारा अनेक महान शक्तियों को प्राप्त करने वाले ऋषि पराशर महान तप और साधना भक्ति द्वारा जीवन के पथ प्रदर्शक के रुप में जाने जाते हैं। वेदव्यास कृष्ण द्वैपायन के पिता महर्षि पराशर जी का दिव्या जीवन चरित्र अत्यंरत अलौकिक व अद्वितीय है, जिन्होंने धर्मशास्त्रम, ज्योरतिष, वास्तुाकला, आयुर्वेद, नीतिशास्त्रर, विषयक ज्ञान मानव मात्र को दिया। महर्षि पराशर रचित ग्रन्थ, वृहत्परा शर होराशास्त्रह, लघुपराशरी, वृहत्प राशरीय धर्म संहिता, पराशर धर्म संहिता, पराशरोदितम, वास्तुशशास्त्र म, पराशर संहिता (आयुर्वेद), पराशर महापुराण, पराशर नीतिशास्त्रस, आदि मानव के लिए कल्याणार्थ रचित ग्रन्थ लोकख्यात हैं। प्राचीन काल के शास्त्रियों में प्रसिद्ध पराशर के नाम पर ऋग्वेद के कई सूक्त हैं। पौराणिक ग्रन्थों के अनुसार ऋषि पराशर के पिता शक्ति मुनि का देहांत इनके जन्म के पूर्व हो चुका था। अतः इनका पालन पोषण इनके पितामह वसिष्ठ ने किया था। यही ऋषि पराशर वेद व्यास कृष्ण द्वैपायन के पिता थे। अपने पितामह वशिष्ठे के द्वारा पालन दृपोषण किये जाने और उनके पास ही रहकर विद्याध्यतयन करने के कारण पराशर वशिष्ठ को ही अपना पिता समझते थे। एक बार पराशर की माता अदृश्यंती ने पराशर से कहा पुत्र जिन्हें तुम पिता कहते हो वे वास्त व में तुम्हारे पिता नहीं पितामह हैं। पराशर के पूछने पर माता अदृश्यन्तीन ने समस्तन जानकारी उन्हें उपलब्ध करा दी कि किस प्रकार तुम्हारे पिता को राक्षस ने तुम्हूारे जन्मश से पूर्व ही मार डाला था।

आज का इतिहास

1502 - दुनिया के सबसे बड़े खोजी यात्री और नयी दुनिया के खोजकर्ता माने जाने वाले क्रिस्टोफर कोलंबस ने एशिया का रास्ता तलाश करने के लिए स्पेन के कादिज से अपनी चौथी यात्रा शुरू की।

1540 - कई सालों तक मुगल शासक अकबर से संघर्ष करने वाले मेवाड़ के महाराणा प्रताप का जन्म।

1653 - विश्वविख्यात ऐतिहासिक इमारत और दुनिया के अजूबों में शुमार ताजमहल का निर्माण 22 वर्ष के निरंतर परिश्रम के बाद पूरा हुआ।

1689 - अंग्रेज शासक विलियम तृतीय ने फ्रांस के साथ युद्ध की घोषणा की।

1866 - महान नेता, समाज सुधारक एवं विचारक गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म।

1874 - बंबई (अब मुंबई) में पहली बार घोड़े से खींची जाने वाली ट्राम कार शुरू हुई।

1946 - डॉ. राम मनोहर लोहिया की अगुआई में गोवा में पुर्तगाल के शासन के खिलाफ पहला सत्याग्रह आंदोलन शुरू हुआ।

1947 - वैश्विक वित्तीय संस्था विश्व बैंक ने अपना पहला ऋण फ्रांस को दिया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पुनर्निर्माण के लिए फ्रांस ने 50 करोड़ डालर का कर्ज मांगा था और 1944 में स्थापित विश्व बैंक ने उसे इससे आधा अर्थात 25 करोड़ डालर का कर्ज दिया।

1955 - पश्चिम जर्मनी नाटो का सदस्य बना और फ्रांस स्थित नाटो मुख्यालय में जर्मनी का ध्वज फहराया गया।

1960 - अमेरिका के खाद्य और औषधि प्रशासन ने पहली गर्भनिरोधक गोली को मंजूरी दी।

1993 - दक्षिण अमेरिकी देश इक्वाडोर के नाम्बिजा क्षेत्र में भूस्खलन से तीन सौ लोगों की मौत।

2000 - जाफना प्रायःद्वीप के एलीफेंट दर्रे पर कब्जे के लिए लिट्टे के साथ हुए संघर्ष में श्रीलंका के 358 सैनिक मारे गये।

2002 - कराची विस्फोट में पाकिस्तान के ही संगठन का हाथ होने के संकेत।

पं बंगाल में शांति व्यवस्था को अराजक हिंसा की चुनौती

मनोज कुमार अग्रवाल

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा की अभूतपूर्व जीत के बाद जिस तरह की हिंसा और तोड़फोड़ की वारदातों की झड़ी लगी है बेशक वो टीएमसी के दबंगई भरे डेड़ दशक के खिलाफ लोगों की नाराजगी और टीएमसी कार्यकर्ताओं की सत्ता छिटकने की हताशा की प्रतिक्रिया हो सकता है लेकिन दोनों राजनीतिक दलों को संयम और समझदारी और सदाचार बनाए रखने की जरूरत है। भाजपा को भाजपा बनाए रखने के लिए इस तरह की अराजकता फैलाने से अपने कार्यकर्ताओं को रोकना ही होगा हालांकि यह हिंसा एकतरफा नही है जिस तरह भाजपा के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी के पीए की बीती रात अज्ञात हमलावरों ने गोली मार कर हत्या की है वह बताता है कि हिंसा और अराजकता का दौर अभी थमने वाला नहीं है। कानून व्यवस्था की स्थिति को सख्ती से सुधारना होगा चुनाव बाद हिंसा में चार से अधिक लोगों की जान जा चुकी है।

मौजूदा चुनाव नतीजों के साथ ही नौ मई को भाजपा सरकार की ताजपोशी की तैयारी शुरू कर दी गई है। इस चुनाव ने राज्य को राजनीति में एक नया इतिहास रच दिया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अभूतपूर्व प्रदर्शन करते हुए प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। राज्य में यह सत्ता बदलने का संकेत नहीं है, बल्कि भारतीय राजनीति में एक बड़े वैचारिक और सामाजिक बदलाव की आहट भी हैं।जितना बडलंबे समय तक ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस को बंगाल की राजनीति का सबसे मजबूत केंद्र माना जाता था।उधर कोलकाता में राज्य के पुलिस डीजीपी ने राज्य में चुनाव परिणाम के बाद आरही हिंसक वारदातों पर उपद्रवियों को कड़ी चेतावनी जारी की है दो सौ उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया है जबकि चार लोगों की हिंसा में मौत हो गई है।

पश्चिम बंगाल में चुनाव परिणाम आने के बाद मंगलवार और बुधवार को हिंसा की कई घटनाएं सामने आई हैं। भाजपा और टीएमसी के पार्टी प्रतिनिधियों ने दावा किया कि पिछले 24 घंटों में पूरे पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई कथित झड़पों में चार लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें पश्चिम बंगाल में चुनाव नतीजों के सामने आने के बाद बुधवार (6 मई) देर रात शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या से हड़कंप मच गया है। अब तक की जांच में सामने आया है कि हत्या में इस्तेमाल की गई गाड़ी पर फर्जी नंबर प्लेट लगी थी। गोली लगने के बाद चंद्रनाथ रथ को विवासिटी हॉस्पिटल लाया गया था, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या के मामले में एक के बाद एक चौंकाने वाली जानकारियां सामने आ रही हैं। पुलिस सूत्रों का दावा है कि घटना रात 10 बजे से 10:15 बजे के बीच हुई। बताया जा रहा है कि हमले के समय गाड़ी की अगली सीट पर चंद्रनाथ रथ और उनका ड्राइवर मौजूद थे। पीछे की सीट पर मिंटू नाम का एक व्यक्ति बैठा था, जिसे चंद्रनाथ रथ का करीबी बताया जा रहा है।सूत्रों के मुताबिक जिस सिल्वर रंग की गाड़ी के जरिए चंद्रनाथ रथ की गाड़ी को रोका गया, उस गाड़ी के चेसिस नंबर मिटा दिए गए थे। यानि हमलावरों ने बहुत बारीकी से इस पूरे हत्याकांड की तैयारी की थी। जांच के फोकस में एक सिल्वर रंग की गाड़ी है, जिससे चंद्रनाथ रथ की गाड़ी को रोका गया था। रात तकरीबन 10 बजकर 20 मिनट पर चंद्रनाथ रथ की गाड़ी मेन हाईवे से उनके घर की गली की तरफ मुड़ी और घर से केवल 100 मीटर की दूरी पर इस गाड़ी को हमलावरों ने चंद्रनाथ रथ की गाड़ी के सामने लगा दिया। इसके बाद बाइक पर सवार एक हमलावर जिसने कैप पहनी हुई थी, उतरता है और ताबड़तोड़ 4 राउंड फायरिंग की। जिसमें से 3 राउंड रथ के सीने में लगा जिससे उनकी मौत हो गई और उनके ड्राइवर की हालत नाजुक है।

गौर करने वाली बात है कि चंद्रनाथ रथ वही शख्स हैं, जिन्होंने पिछले दिनों चुनाव के दौरान शुभेंदु अधिकारी का प्रतिनिधित्व करते हुए कई जगह देखे गए थे। जब ममता बनर्जी भवानीपुर के स्ट्रॉन्ग रूम में दाख़िल हुईं, तो चंद्रनाथ रथ बीजेपी समर्थकों के साथ वहां पहुंच गए थे। चंद्रनाथ रथ (42) बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के सहायक थे। चंद्रनाथ, शुभेंदु गृह के जिले पूर्वी मिदनापुर के चांदीपुर के रहने वाले थे। चंद्रनाथ भारतीय वायु सेना के पूर्व अधिकारी हैं। उन्होंने साल 2019 में शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक के तौर पर काम शुरू किया था, जब शुभेंदु ममता बनर्जी की सरकार में मंत्री थे। दिलचस्प बात यह है कि बंगाल चुनाव की मतगणना से ठीक तीन दिन पहले 30 अप्रैल को जब ममता बनर्जी शाख़ावत मेमोरियल हाई स्कूल स्थित भवानीपुर के स्ट्रॉन्ग रूम में दाख़िल हुईं, तो चंद्रनाथ रथ बीजेपी समर्थकों के साथ वहां पहुंच गए थे। शुभेंदु अधिकारी की गैर-मौजूदगी में वे मतगणना केंद्र के बाहर हो रहे विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे, क्योंकि शुभेंदु उस रात पूर्वी मिदनापुर स्थित अपने गृह नगर कांथी के लिए रवाना हो चुके थे।

जैसा कि आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल चुनाव परिणाम के बाद ये आशंका ज़ाहिर की जा रही थी कि हिंसक घटनाएं हो सकती हैं। राज्य में तोड़फोड़ और हिंसा की कई ख़बरें आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने बयान जारी कर आरोप लगाया था कि तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के लोग अपनी पहचान बदलकर ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और इन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

एक रिपोर्ट के मुताबिक भाजपा के एक पार्टी प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि जहां उत्तरी 24 परगना के न्यू टाउन और हावड़ा के उदय नारायणपुर में भाजपा के दो कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई। वहीं टीएमसी ने कहा कि कोलकाता के बेलेघाटा और बीरभूम के नानूर में उसके दो सदस्यों की हत्या हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक भाजपा कार्यकर्ता मधु मंडल की हत्या तब कर दी गई, जब वह न्यू टाउन में पार्टी की जीत की रैली में शामिल होने के बाद घर लौट रहे थे। हावड़ा के उदयनारायणपुर में भाजपा कार्यकर्ता यादव बार की हत्या कर दी गई। टीएमसी के प्रवक्ता जय प्रकाश मजूमदार ने कहा, अब तक हमारे दो कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है, एक बीरभूम में और दूसरा कोलकाता में। बीरभूम में, पीड़ित की पहचान पार्टी सदस्य अबीर शेख के रूप में हुई, जबकि बेलेघाटा में टीएमसी कार्यकर्ता बिस्वजीत पटनायक की हत्या कर दी गई

पुलिस ने अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं की है कि ये मौतें राजनीति से जुड़ी थीं या नहीं। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने, जिन्होंने अपना नाम न बताने की शर्त पर बात की, कहा कि कम से कम दो मामले राजनीतिक नहीं थे।अधिकारी ने कहा, शुरुआती जांच से पता चलता है कि हावड़ा में हुई हत्या राजनीतिक नहीं थी। यह निजी दुश्मनी के कारण हुई थी। बेलेघाटा में, पीड़ित छत से कूद गया, जब कुछ लोग उसे ढूंढते हुए उसके दरवाजे पर आए और वह भागने की कोशिश कर रहा था। कोलकाता पुलिस कमिश्नर अजय कुमार नंद ने कहा, कोलकाता के हॉग मार्केट में बुलडोजर से जुड़ी जो घटना हुई है, उस पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आगे कहा, एक हत्या हुई है, लेकिन यह गैंगवार का मामला है। इसका राजनीति से कोई लेना-देना नहीं है। एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। एक वरिष्ठ चुनाव अधिकारी ने कहा, चुनाव आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और राज्य में तैनात केंद्रीय पुलिस बल को निर्देश दिया है कि वे राज्य में चुनाव के बाद होने वाली हिंसा के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति सुनिश्चित करें।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक आदित्य वशिष्ठ द्वारा सांई प्रिंटिंग प्रेस, बी-42 सेक्टर-7 नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) उत्तर प्रदेश-201301 से मुद्रित व बी-142/2, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली-110065 से प्रकाशित।
संपादकीय एवं संपर्क कार्यालय ए-152 सेक्टर-63, नोएडा-201301 संपादक - आदित्य वशिष्ठ कानूनी सलाहकार-पवित्र मोहन शर्मा आर.एन.आई. DELHIN/2012/42452
इस अंक में प्रकाशित सभी समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी एक्ट के अंतर्गत संपादक उत्तरदायी होंगे। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन होंगे। e-mail: Jbttimes2021@ gmail. Com

तीनों सेनाओं के कमांडरों ने जयपुर में साइबर और स्पेस युद्ध पर किया गहन मंथन

दो दिन की कमांडर्स कांफ्रेंस के आखिरी दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हुए शामिल

नई दिल्ली। तीनों सेनाओं के कमांडर भविष्य के साइबर और स्पेस युद्ध पर चर्चा करने के लिए जयपुर में इकट्ठा हुए। सेना की दक्षिणी-पश्चिमी कमान के नेतृत्व में हुई दो दिन की कमांडर्स कांफ्रेंस में नवाचार, स्वदेशीकरण और नागरिक-सैन्य संलयन के जरिए आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कमांडरों से कहा कि वे देश के दुश्मनों के लिए 'एलीमेंट ऑफ सरप्राइज' को बढ़ावा दें, ताकि वे किसी भी स्थिति में रणनीतिक बढ़त हासिल कर सकें।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जयपुर में 'नए डोमेन में मिलिट्री कैपेबिलिटी' विषय पर हुई दो दिनों की कॉन्फ्रेंस के आखिरी दिन शुक्रवार को शामिल हुए। 'ऑपरेशन सिंदूर' की पहली सालगिरह मनाने के लिए जयपुर पहुंचे रक्षा मंत्री ने कॉन्फ्रेंस के पहले दिन ऑपरेशन सिंदूर पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म रिलीज की। उन्होंने विजन 2047 और इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन आर्किटेक्चर और एयर डिफेंस के लिए जॉइंट डॉक्ट्रिन भी रिलीज किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेनाओं के कमांडरों से कहा कि वे ऑपरेशन सिंदूर और मौजूदा ग्लोबल सुरक्षा हालात से सीखकर भविष्य के लिए तैयार रहें। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को कम समय का गहराई तक जाने वाला हाई-इंटेंसिटी और हाई-इम्पैक्ट ऑपरेशन बताया, जिसने दिखाया कि भारत अपने दुश्मन को सरेंडर करने पर मजबूर कर सकता है।

उन्होंने कहा कि यह ऑपरेशन भारत की बढ़ती क्षमताओं का प्रदर्शन और नए सैन्य मूल्यों का प्रतीक था। रक्षा मंत्री ने तेजी से बदलते भू-राजनीतिक सुरक्षा परिदृश्य में तैयार रहने की जरूरत पर जोर दिया। उभरती टेक्नोलॉजी के बदलाव लाने वाले असर पर रेखांकित करते हुए उन्होंने संघर्ष के सभी पहलुओं में एक साथ देश की तैयारी पक्की करने की अहमियत पर जोर दिया। राजनाथ सिंह ने तीनों सेनाओं में संयुक्तता, एकीकरण और प्रौद्योगिकी अपनाने को बढ़ाने में हुई तरक्की की तारीफ की। उन्होंने कहा कि वैश्विक रक्षा क्षेत्र में हो रहे बड़े बदलावों में संयुक्तता एक अहम हिस्सा है। उन्होंने कहा कि भविष्य के युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं, बल्कि नई सोच और बेहतर तालमेल से जीते जाएंगे।

उन्होंने दुश्मन के एलिमेंट ऑफ सरप्राइज से सावधान रहने और हमेशा दो कदम आगे रहने को कहा। उन्होंने हथियारों और प्लेटफॉर्म के जरिए रक्षा बलों की क्षमताओं को बढ़ाने के वादे को दोहराया। उन्होंने कहा कि खास डोमेन में रिसर्च पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कार्यक्रम में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, नौसेना स्टाफ के प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी, सेना स्टाफ के प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह, रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह, रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव और डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉ. समीर वी कामत, सचिव (रक्षा उत्पादन) संजीव कुमार, सचिव (पूर्व सैनिक कल्याण) सुकृति लिखी, सचिव (रक्षा वित्त) विश्वजीत सहाय और अन्य वरिष्ठ नागरिक और सैन्य अधिकारी शामिल हुए।

मनोहर लाल खट्टर ने IIT रुड़की में रेगुलेटरी सेंटर का किया उद्घाटन

हरिद्वार। केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आईआईटी रुड़की में 'सेंटर फॉर रेगुलेटरी अफेयर्स' का उद्घाटन किया। यह केंद्र फोरम ऑफ रेगुलेटर्स और आईआईटी रुड़की की संयुक्त पहल है, जिसका उद्देश्य देश के विद्युत क्षेत्र की नियामकीय व्यवस्था को और अधिक मजबूत, पारदर्शी एवं भविष्य के अनुरूप बनाना है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बढ़ती बिजली मांग, नवीकरणीय ऊर्जा के तेजी से विस्तार, डिजिटल तकनीकों के बढ़ते उपयोग और ऊर्जा बाजारों में हो रहे बदलावों को देखते हुए मजबूत नियामकीय ढांचे की आवश्यकता पहले से अधिक बढ़ गई है। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह केंद्र रेगुलेटरी सैंडबॉक्सिंग और डिमांड फ्लेक्सिबिलिटी जैसे विषयों पर महत्वपूर्ण शोध और नीति निर्माण में सहयोग करेगा। उन्होंने बताया कि यह देश में इस प्रकार का दूसरा केंद्र है।

इससे पहले आईआईटी दिल्ली में भी केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग और ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड के सहयोग से एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जा चुका है। कार्यक्रम में केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग एवं फोरम ऑफ रेगुलेटर्स के अध्यक्ष जिष्णु बरुआ ने कहा कि यह केंद्र देश में नियामकीय क्षमता निर्माण का प्रमुख संस्थान बनेगा और उच्च गुणवत्ता वाले शोध एवं ज्ञान संसाधनों के माध्यम से भारत की ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व क्षमता को मजबूत करेगा।

आकाशवाणी ने मैराथन के जरिए मनाया नौ दशकों की यात्रा का जश्न

नई दिल्ली। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में शुक्रवार को यहां आकाशवाणी मुख्यालय से मैराथन का आयोजन किया गया। इसको प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) गौरव द्विवेदी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसमें 500 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गौरव द्विवेदी ने कहा कि आकाशवाणी का अपना एक समृद्ध इतिहास रहा है और अटूट विश्वास है कि भविष्य में भी इसकी आवाज इसी तरह गूंजती रहेगी। इसका कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य राष्ट्रीय प्रसारक के साथ एकजुटता दिखाते हुए फिट इंडिया की भावना को बढ़ावा देना था। लगभग 3.5 किलोमीटर लंबी ये मैराथन आकाशवाणी भवन से शुरू होकर कृषि भवन, रेल भवन तथा आरबीआई भवन से होते हुए वापस आकाशवाणी भवन पर समाप्त हुई। इस आयोजन में आकाशवाणी के कर्मचारियों के साथ-साथ भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) और सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) जैसे अर्धसैनिक बलों के जवानों ने भी दौड़ लगाकर फिट इंडिया की भावना को प्रदर्शित किया। मैराथन में विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विजेताओं को ट्रॉफी और पदक से सम्मानित किया गया। इनमें पुरुषों में हेमकिशोर (एसएसबी) प्रथम, आनंद (एसएसबी) द्वितीय और स्टैनजिन जेकमेट (आईटीबीपी) तृतीय स्थान पर रहे जबकि महिलाओं में भूमिका वार्ष्णेय (सीआईएसएफ) प्रथम, कमलेश बाली (सीआईएसएफ) द्वितीय और स्नेहा (एसएसबी) तृतीय स्थान विजेता रहीं। वहीं, आकाशवाणी के कर्मचारियों में मुरुगन ने प्रथम, सोमपाल ने द्वितीय और रणधीर ठाकुर ने तृतीय स्थान प्राप्त किया।

अन्य सभी प्रतिभागियों को उनके उत्साहवर्धन के लिए भागीदारी पदक दिए गए। इस कार्यक्रम को आयोजित करने का उद्देश्य 1936 में स्थापित ऑल इंडिया रेडियो की अब तक की अपनी यात्रा का जश्न मनाना रहा। इस दौरान आकाशवाणी के आदर्श वाक्य ₹बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय₹ के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराते हुए आने वाले दशकों में भी राष्ट्र की निरंतर सेवा करने का संकल्प लिया। इस मौके पर प्रसार भारती के कार्मिक सदस्य राजीव भारद्वाज तथा आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन सहित अन्य अधिकारी गण और प्रतिभागी मौजूद रहे।

देश में पेट्रोल की कीमतें लगभग 94.77 रुपये प्रति लीटर पर स्थिर

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को कहा कि पश्चिम एशिया में जारी संकट के बावजूद भारत में पेट्रोल की कीमतें लगभग 94.77 रुपये प्रति लीटर बनी हुई हैं, जबकि जर्मनी, फ्रांस और यूके जैसे देशों में ये कीमतें लगभग 200 रुपये प्रति लीटर हैं।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने नई दिल्ली में अंतर-मंत्रालयी प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया की लगभग 20 फीसदी ऊर्जा हॉर्मुज जलडमरूमध्य क्षेत्र से होकर गुजरती है, जिससे यह भारत के लिए बेहद अहम हो जाता है। भारत अपने कच्चे तेल का लगभग 40 फीसदी, एलपीजी का 90 फीसदी और प्राकृतिक गैस का 65 फीसदी हिस्सा मध्य-पूर्व से ही आयात करता है। उन्होंने कहा कि वैश्विक कीमतों में बढ़ोतरी के चलते कच्चे तेल की कीमत लगभग 70 डॉलर से बढ़कर लगभग 120 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई है, जबकि एलपीजी की कीमतों में भी भारी उछाल आया है। उन्होंने कहा कि तेल विपणन कंपनियों को हो रहे नुकसान के बावजूद, भारत सरकार ने उत्पाद शुल्क में कटौती करके एलपीजी उत्पादन बढ़ाकर, पीएनजी कनेक्शन को बढ़ावा देकर और गैस की स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करके उपभोक्ताओं को सुरक्षा प्रदान करने का काम किया है। सुजाता शर्मा ने बताया कि भारत में पेट्रोल की कीमतें लगभग 94.77 रुपये प्रति लीटर बनी हुई हैं, जबकि जर्मनी, फ्रांस और यूके जैसे देशों में ये कीमतें लगभग 200 रुपये प्रति लीटर हैं। सरकार ने एलपीजी की निर्बाध आपूर्ति भी सुनिश्चित की है, जिससे किसी भी वितरक को किसी तरह की कमी का सामना नहीं करना पड़ा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के निर्देश पर खाड़ी क्षेत्र के साथ भारत का संपर्क उच्चतम स्तर पर जारी है।

विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की यूएई यात्राओं के बाद विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने 7 मई, 2026 को संयुक्त अरब अमीरात का दौरा किया। भारत ने कतर और सऊदी अरब सहित अन्य खाड़ी साझेदारों के साथ भी संपर्क बनाए रखा। उन्होंने कहा कि इस यात्रा के दौरान विदेश सचिव ने यूएई की राज्य मंत्री और भारत के लिए विशेष दूत, रीम अल हाशिमी के साथ बातचीत की और खलदून अल मुबारक से मुलाकात की। चर्चाओं का मुख्य केंद्र व्यापार, निवेश, रक्षा, फिनटेक, स्वास्थ्य सेवा और पश्चिम एशिया में क्षेत्रीय घटनाक्रम रहे। जायसवाल ने कहा कि उन्होंने मार्टिन ब्रिएन्स के साथ भारत-फ्रांस-यूएई त्रिपक्षीय बैठक में भी भाग लिया, जहां तीनों पक्षों ने अपनी साझेदारी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और निर्धारित समय-सीमाओं के साथ एक व्यवस्थित रूपरेखा पर सहमति व्यक्त की। बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक ओपेश कुमार शर्मा ने कहा कि बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय, नाविकों के कल्याण और समुद्री संचालन में कोई रुकावट न आए, यह सुनिश्चित करने के लिए विदेश मंत्रालय, भारतीय मिशनों और समुद्री क्षेत्र से जुड़े लोगों के साथ लगातार समन्वय बनाए हुए है।

उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में मौजूद सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं, और पिछले 48 घंटों में किसी भी ऐसे जहाज से जुड़ी कोई घटना सामने नहीं आई है, जिस पर भारतीय झंडा लगा हो या जिस पर भारतीय नाविक सवार हों। ओपेश कुमार शर्मा ने बताया कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ़ शिपिंग में बनाए गए कंट्रोल रूम ने शुरू होने के बाद से अब तक 8,737 से ज्यादा कॉल और 19,314 ईमेल संभाले हैं; इनमें से 167 कॉल और 582 ईमेल तो अकेले पिछले 48 घंटों में आए हैं। मंत्रालय ने अब तक 3,019 से ज्यादा भारतीय नाविकों की सुरक्षित वतन वापसी में भी मदद की है; इनमें से 20 नाविक पिछले 48 घंटों में खाड़ी क्षेत्र के अलग-अलग स्थानों से वापस लौटे हैं। पूरे भारत में समुद्री संचालन सामान्य रूप से जारी है, और कहीं भी जहाजों की भीड़ या रुकावट की कोई ख़बर नहीं है।

इसके अलावा विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव (खाड़ी), असीम आर. महाजन ने बताया कि विदेश मंत्रालय खाड़ी और पश्चिम एशिया क्षेत्र में हो रहे घटनाक्रमों पर लगातार बारीकी से नजर रख रहा है। हमारे प्रयासों का मुख्य उद्देश्य इस क्षेत्र में रहने वाले भारतीय समुदाय की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करना है। उन्होंने बताया कि मंत्रालय में स्थापित एक विशेष कंट्रोल रूम पूरी तरह से कार्यरत है, जो भारतीय नागरिकों और उनके परिवारों की पूछताछ का जवाब देने के लिए समर्पित है। सूचनाओं के आदान-प्रदान और अपने प्रयासों में समन्वय स्थापित करने के लिए हम राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ निरंतर संपर्क में हैं।

ऑर्गेनिक खेती, स्थानीय वैल्यू चेन और ग्रामीण उद्यमिता में पूर्वोत्तर के सहकारी क्षेत्र में अपार संभावनाएं

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के "सहकार से समृद्धि" के विजन से प्रेरित तथा केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में देशभर में चलाए जा रहे सहकारी सुधार अभियानों के अंतर्गत सहकारिता मंत्रालय ने आज मिजोरम के आइजोल में सहकारी सुधारों पर दूसरे क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। यह सम्मेलन देशभर में आयोजित की जा रही क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय कार्यशालाओं की श्रृंखला का हिस्सा है। उद्देश्य जमीनी स्तर पर सहकारी संस्थानों को सशक्त बनाना तथा सहकारी संस्थानों आधारित विकास को गति देना है। इस पहल के अंतर्गत पहला क्षेत्रीय सम्मेलन इससे पहले जयपुर में आयोजित किया गया था। यह सम्मेलन मिजोरम में पहली बार आयोजित किया गया क्षेत्रीय सहकारी सुधार सम्मेलन भी रहा, जो सहकारिता मंत्रालय के उस सतत प्रयास को दर्शाता है जिसके तहत सहकारी आंदोलन को देश के अंतिम छोर तक पहुँचाया जा रहा है तथा पूर्वोत्तर के दूरस्थ और भौगोलिक रूप से चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों तक सहकारी सुधारों का विस्तार किया जा रहा है।

मंत्रालय ने रेखांकित किया कि सहकारी विकास अब पारंपरिक क्षेत्रों से आगे बढ़ते हुए सीमावर्ती और दूरदराज ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुँच रहा है तथा सहकारी संस्थानों आधारित आर्थिक मॉडलों के माध्यम से स्थानीय समुदायों के लिए नए अवसर उत्पन्न कर रहा है।

इस क्षेत्रीय सम्मेलन में सहकारिता मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों, पूर्वोत्तर के सभी राज्यों असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम के प्रतिनिधियों के साथ-साथ नाबार्ड, एनसीडीसी, नैफेड, एनसीसीएफसी, एनडीडीबी,एनईडीएफआई तथा विभिन्न सहकारी संस्थानों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

यशोदा मेडिसिटी में समर्पित थैलेसीमिया केयर सेंटर का शुभारंभ

❖ जनभावना टाइम्स

गाजियाबाद। इंटरनेशनल थैलेसीमिया दिवस के अवसर पर यशोदा मेडिसिटी ने थैलेसीमिया मरीजों के लिए एक समर्पित थैलेसीमिया केयर सेंटर लॉन्च किया। इस सेंटर का उद्देश्य थैलेसीमिया से पीड़ित मरीजों और उनके परिवारों को एक ही स्थान पर संपूर्ण, व्यवस्थित और दीर्घकालिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना है।इस सेंटर का उद्घाटन कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में किया।

इस अवसर को क्षेत्र में विशेष रक्त रोग सेवाओं के विकास की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। अस्पताल प्रबंधन के अनुसार यह सेंटर विशेष रूप से थैलेसीमिया मरीजों की जटिल और लंबी अवधि की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। यहां विशेषज्ञ हेमेटोलॉजी सेवाएं, डे-केयर ब्लड ट्रांसफ्यूजन सुविधा, आयरन चेलेशन थेरेपी, एडवांस जांच, बोन मैरो ट्रांसप्लांट मूल्यांकन, जेनेटिक काउंसलिंग, पोषण एवं मानसिक स्वास्थ्य सहायता जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।कार्यक्रम के दौरान थैलेसीमिया मास्टरक्लास और रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें नियमित एवं स्वैच्छिक रक्तदान के महत्व पर जोर दिया गया। डॉक्टर पी. न. अरोड़ा ने कहा कि थैलेसीमिया मरीजों को जीवनभर नियमित ब्लड ट्रांसफ्यूजन और निरंतर देखभाल की आवश्यकता होती है। ऐसे में यह समर्पित सेंटर मरीजों को बेहतर जीवन गुणवत्ता और आधुनिक उपचार उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

वहीं डॉक्टर निवेदिता ढींगरा ने बताया कि आधुनिक ट्रांसफ्यूजन प्रोटोकॉल, संक्रमण नियंत्रण और बोन मैरो ट्रांसप्लांट तकनीकों की मदद से अब थैलेसीमिया मरीज बेहतर जीवन जी सकते हैं। उन्होंने कहा कि सेंटर में सभी जरूरी सुविधाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराई गई हैं ताकि मरीजों को समन्वित और प्रभावी उपचार मिल सके। अस्पताल प्रबंधन ने बताया कि यह पहल इलाज के साथ-साथ जागरूकता और रोकथाम पर भी केंद्रित है। इसके तहत कैरियर स्क्रीनिंग, विवाह पूर्व काउंसलिंग और गर्भावस्था के दौरान जांच को बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि आने वाली पीढ़ियों को थैलेसीमिया जैसी अनुवांशिक बीमारी से बचाया जा सके।

कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा ने बताया कि यशोदा हॉस्पिटल ने काफी तरक्की की है जबकि आधुनिक मशीन इस अस्पताल में एक ही छत के नीचे सभी तरह के डॉक्टर उपलब्ध है जैसे कि दिल्ली में एम्स हॉस्पिटल की तर्ज पर गाजियाबाद में यशोदा मेडिसिटी हॉस्पिटल काम कर रहा है।

बिहार में निवेश और व्यापार सुधारों पर मंथन

डीरेगुलेशन 2.0 को मिशन मोड में लागू करने के निर्देश

पटना। पटना स्थित मुख्य सचिवालय सभाकक्ष में शुक्रवार को केंद्र सरकार के कैबिनेट सचिवालय के विशेष सचिव केके पाठक और बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की संयुक्त अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

बैठक में राज्य में निवेश को बढ़ावा देने, व्यापार सुगमता में सुधार और पुराने व अप्रासंगिक कानूनों को समाप्त करने के उद्देश्य से 'वि-विनियमन (डीरेगुलेशन) 1.0 एवं 2.0' की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में विशेष सचिव केके पाठक ने सभी विभागों को निर्देश दिया कि वे अपने कार्यक्षेत्र में अनावश्यक अनुपालन बोझ को कम करें और 'डीरेगुलेशन 2.0' के तहत चिन्हित सुधारों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूरा करें। बैठक के दौरान बुनियादी ढांचे के विकास में सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए स्थिरता पर राष्ट्रीय भवन संहिता (नेशनल बिल्डिंग कोड ऑन सस्टेनेबिलिटी) (एनबीसीएस) 2026 के नए मानकों को राज्य के बिल्डिंग बाई-लॉज में शामिल करने पर भी विस्तृत चर्चा हुई।

राज्य में शहरी नियोजन को आधुनिक और प्रभावी बनाने के लिए फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) नियमों को तर्कसंगत बनाने तथा सरकारी संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन के लिए संपूर्ण सुविधा प्रबंधन (टोटल फैसिलिटी मैनेजमेंट) (टीएफएम) मॉडल अपनाने के निर्देश दिए गए। बैठक के दौरान केके पाठक ने अधिकारियों से कहा कि विभाग ऐसे सभी नियमों, रिटर्न और रजिस्टरों की सूची तैयार करें जिन्हें समाप्त किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक अनावश्यक नियम निवेश और उद्योग के विकास में बाधा बनता है।

उन्होंने निर्देश दिया कि 'डीरेगुलेशन 2.0' के अंतर्गत लंबित सभी कार्यों को अगले 15 कार्य दिवसों के भीतर पूरा कर पोर्टल पर अपलोड किया जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही या शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी। विशेष सचिव ने यह भी कहा कि व्यावसायिक कानूनों के तहत छोटी तकनीकी चूकों के लिए कारावास जैसे कठोर प्रावधानों को हटाकर उन्हें आर्थिक दंड में बदलने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए।

साथ ही यदि कोई सुधार एक से अधिक विभागों से जुड़ा हो तो कैबिनेट सचिवालय विभाग समन्वय की भूमिका निभाए, ताकि फाइलों के निपटारे में देरी न हो। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी विभागीय नोडल अधिकारी प्रत्येक शुक्रवार को अपनी प्रगति रिपोर्ट कैबिनेट सचिवालय को उपलब्ध कराएं, जिसकी समीक्षा सीधे मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा की जाएगी।

बंगाल की जनता का विश्वास टूटने नहीं देंगे : अमित शाह

कोलकाता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) बंगाल की जनता का विश्वास टूटने नहीं देगी। शुक्रवार को कोलकाता के विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में भाजपा विधायक दल की बैठक के बाद संवाद माध्यमों को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि भाजपा और नरेंद्र मोदी पर भरोसा करके बंगाल की जनता ने जो प्रचंड जीत दी है, उसके लिए मैं आभारी हूं। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि आपका विश्वास डिगे नहीं। हम सोनार बंगाल के लक्ष्य को जारी रखेंगे। गृह मंत्री ने भरोसा दिलाया कि इसके बाद घुसपैठ और गौ तस्करी नहीं हो सकेगी।

उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटरों को पोस्टपेड में बदलने का आदेश जारी: ऊर्जा मंत्री शर्मा

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर प्रणाली को बंद करने और संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के तहत स्थापित सभी स्मार्ट मीटरों को तत्काल प्रभाव से पोस्टपेड में बदलने का फैसला किया है। इसके बाद उपभोक्ताओं को बिजली इस्तेमाल करने के बाद बिल मिलेगा।

मई 2026 की खपत का बिल जून 2026 में पोस्टपेड प्रणाली के तहत जारी किया जाएगा। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने शुक्रवार को कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने विद्युत उपभोक्ताओं की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए प्रदेश में संचालित स्मार्ट प्री-पेड मीटर व्यवस्था को समाप्त कर सभी स्मार्ट मीटरों को पोस्टपेड मोड में संचालित करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में औपचारिक आदेश जारी कर दिए गए हैं। पूर्वांचल, मध्यांचल, दक्षिणांचल, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगमों और केस्को कानपुर में लागू यह व्यवस्था उपभोक्ताओं को बड़ी राहत प्रदान करेगी। ऊर्जा मंत्री ने एक बयान में कहा कि उपभोक्ताओं को बिल एसएमएस और व्हाट्सएप के जरिये उपलब्ध कराया जाएगा। स्मार्ट पोस्टपेड बिल प्रत्येक माह की 10 तारीख तक जारी किए जाएंगे।

जिन क्षेत्रों में नेटवर्क अथवा संचार संबंधी समस्या के कारण स्मार्ट मीटर की स्वतः रीडिंग प्राप्त नहीं होगी, वहां एएमआईएसपी एजेंसियों के माध्यम से 'मैनुअल रीडिंग' लेकर समय से बिल उपलब्ध कराया जाएगा। मंत्री ने कहा कि जिन उपभोक्ताओं के मोबाइल नंबर पंजीकृत नहीं हैं या गलत दर्ज हैं, उनके लिए विमरण कंपनियों के स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा। साथ ही उपभोक्ता संबंधित विद्युत वितरण निगम के व्हाट्सएप चैटबॉट एवं 1912 हेल्पलाइन के माध्यम से भी अपना बिल प्राप्त कर सकेंगे। प्रदेश में अब सभी नए विद्युत संयोजन स्मार्ट पोस्टपेड मोड में ही जारी किए जाएंगे। पूर्व में प्री-पेड व्यवस्था लागू होने के दौरान समायोजित की गई सुरक्षा धनराशि को अब विद्युत प्रदाय संहिता-2005 एवं कॉस्ट डाटा बुक-2026 के प्रावधानों के अनुसार चार समान मासिक किस्तों में उपभोक्ताओं के बिलों में जोड़ा जाएगा।

ऊर्जा मंत्री ने कहा कि पोस्टपेड उपभोक्ताओं को पूर्व की भांति बिल जारी होने की तारीख से 15 दिन का भुगतान समय और उसके बाद सात दिन की डिस्कनेक्शन अवधि प्रदान की जाएगी। निर्धारित समय तक भुगतान न होने पर विद्युत प्रदाय संहिता एवं शुल्क आदेश के अनुसार विलंब अधिभार लागू होगा।

घरेलू उपभोक्ताओं को विशेष राहत देते हुए 30 अप्रैल 2026 तक के बकाया विद्युत बिल को 10 आसान किस्तों में जमा करने की सुविधा प्रदान की गई है। जबकि अन्य श्रेणी के उपभोक्ताओं को 40, 30 और 30 प्रतिशत की तीन किस्तों में भुगतान की सुविधा मिलेगी। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि स्मार्ट मीटर एवं बिजली बिलों से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए 15 मई 2026 से 30 जून 2026 तक अधिशासी अभियंता एवं उपखंड अधिकारी कार्यालयों पर विशेष कैंप एवं सहायता केंद्र लगाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त 1912 हेल्पलाइन पर भी विशेष व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है, ताकि उपभोक्ताओं की समस्याओं का त्वरित समाधान हो सके।

पुलिसिंग के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत रहना जरूरी: एसपी

देवरिया। पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर. शंकर ने शुक्रवार को रिजर्व पुलिस लाइन में आयोजित साप्ताहिक परेड की सलामी लेकर पुलिस बल की कार्यक्षमता, अनुशासन एवं व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जवानों को शारीरिक एवं मानसिक रूप से फिट रहने के लिए प्रेरित करते हुए दौड़ भी लगवाई।

टोलीवार ड्रिल कराकर अनुशासन और एकरूपता का अभ्यास कराया। पुलिस अधीक्षक ने पुलिस कर्मियों से कहा कि बेहतर पुलिसिंग के लिए शारीरिक फिटनेस के साथ मानसिक रूप से भी मजबूत रहना आवश्यक है। इसी उद्देश्य से सभी पुलिसकर्मियों की दौड़ लगवाई गई, जिससे उनमें ऊर्जा और सक्रियता बनी रहे। सामूहिक समन्वय और अनुशासन बनाए रखने के लिए टोलीवार ड्रिल भी कराई गई। एसपी ने जवानों को निर्देशित किया कि नियमित अभ्यास और अनुशासित दिनचर्या से ही बेहतर कार्य क्षमता विकसित होती है। परेड के उपरांत पुलिस अधीक्षक ने रिजर्व पुलिस लाइन परिसर स्थित विभिन्न शाखाओं का निरीक्षण किया।

उन्होंने क्वार्टर गार्द, एमटी शाखा, यूपी-112 पीआरवी, मनोरंजन कक्ष, जिला मेस, स्टोर तथा आरटीसी मेस का भ्रमण कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान यूपी-112 पीआरवी में मौजूद दंगा नियंत्रण उपकरणों, फर्स्ट ऐड किट तथा अन्य आवश्यक संसाधनों की गहन जांच की गई।

एसपी ने संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देश दिए कि सभी उपकरणों की नियमित साफ-सफाई, समुचित देखरेख तथा समय-समय पर उनकी जांच सुनिश्चित की जाए, ताकि आपात स्थिति में उनका प्रभावी उपयोग किया जा सके। उन्होंने उपकरणों के कुशल संचालन पर भी विशेष जोर दिया। निरीक्षण के दौरान गार्द कमांडरों एवं विभिन्न शाखाओं के रजिस्टरों और अभिलेखों का भी अवलोकन किया गया। पुलिस अधीक्षक ने समस्त रजिस्टरों को व्यवस्थित रखने और अभिलेखों को अद्यावधिक बनाए रखने के निर्देश दिए।

नेपाल के कैसिनो, भारतीय युवाओं की बर्बादी के नये अड्डे

बहराइच। 'चमकती रोशनी में कितने घर उजड़ गए, कुछ लोग खेलते रहे, कई सपने बिखर गए।' नेपाल के बांके जिले में संचालित कैसिनो अब केवल मनोरंजन का साधन नहीं रह गए हैं, बल्कि भारतीय युवाओं की बर्बादी का नया दरवाज़ा बन चुके हैं।

भारत-नेपाल सीमा से सटे इन कैसिनो में ताश, शराब और नशे की चकाचौंध ने उत्तर प्रदेश समेत देश के विभिन्न राज्यों के युवाओं को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। इस गंदी लत के कारण अपनी जमा पूंजी गंवा कर कर्ज, नशे और बर्बादी के दलदल में धंसते जा रहे युवाओं को देश के विरुद्ध अपराधों में इस्तेमाल किये जाने का खतरा है। उत्तर प्रदेश के बहराइच से सटे नेपाल में नेपालगंज मुख्यालय को कैसिनो का हब माना जाता है, जहां दर्जनों कैसिनो भारतीय सैलानियों को आकर्षित करने के लिए संचालित हो रहे हैं। बहराइच, लखनऊ, सीतापुर, बलरामपुर, गोंडा, कानपुर, लखीमपुर, शाहजहांपुर, श्रावस्ती समेत कई जिलों के युवा यहां जुए की लत में पड़कर कर्ज में डूब गए हैं या कंगाली की कगार पर पहुंच गए हैं। सुबह सीमा पार जाने के लिए युवाओं की भीड़ रहती है और शाम ढलते ही वे खाली हाथ लौटते दिखाई देते हैं। सूत्रों के अनुसार, पांच से दस लाख रुपये तक दांव लगाने वाले युवाओं को कैसिनो प्रबंधन उनके शहर से नेपालगंज तक लाने-ले जाने की सुविधा भी देता है। हारने की स्थिति में उन्हें घर तक छोड़ने की व्यवस्था की जाती है। कैसिनो में भारतीयों को मुफ्त शराब और बीयर परोसी जाती है, वहीं नृत्यांगनाओं द्वारा मनोरंजन भी कराया जाता है।

जानकारी के मुताबिक, सीमा से लगे पांच से दस किलोमीटर के दायरे में दर्जनों कैसिनो संचालित हो रहे हैं, जिनमें नेपालियों का प्रवेश पूरी तरह वर्जित है। यहां केवल भारतीय और विदेशी नागरिकों को ही प्रवेश दिया जाता है। हर रोज करोड़ों रुपये की भारतीय मुद्रा कैसिनो में खपाई जा रही है, जिसमें सर्वाधिक उपयोग पांच सौ रुपये के नोट का हो रहा है। स्थानीय पुलिस और एसएसबी का दावा है कि सीमा पर सतत निगरानी रहती है और बिना जांच-पड़ताल के कोई भी व्यक्ति सीमा पार नहीं कर सकता।

बावजूद इसके, बड़ी संख्या में भारतीय युवा कैसिनो की ओर आकर्षित हो रहे हैं। सुरक्षा विशेषज्ञों को चिंता है कि समय रहते इस पर अगर रोक नहीं लगी तो जुए में बर्बाद युवाओं को अपराधों के रास्ते पर धकेले जाने की आशंका है। उनका कहना है कि नेपाल में पाकिस्तानी, चीनी एवं अन्य विदेशी खुफिया एजेंसियों का जाल फैला हुआ है और जुए में बर्बाद युवाओं को फंसा कर राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ उनका इस्तेमाल किया जा सकता है।

वर्ष 2017 से पहले बदहाल स्थिति में था होमगार्ड विभाग योगी सरकार ने दिया सम्मान : प्रजापति

पिछली सरकारों ने होमगार्ड जवानों को उपेक्षित रखा, ऐतिहासिक फैसले ले रही भाजपा सरकार

मीरजापुर। उत्तर प्रदेश के होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) धर्मवीर प्रजापति ने शुक्रवार को विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि वर्षों तक सत्ता में रहने वाली सरकारों ने होमगार्ड जवानों को केवल इस्तेमाल किया, लेकिन उनके हितों और सुविधाओं की कभी चिंता नहीं की।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पहली बार होमगार्ड जवानों के सम्मान, सुरक्षा और सुविधाओं को प्राथमिकता दी गई है। राज्यमंत्री धर्मवीर प्रजापति शुक्रवार को विंध्याचल के कलना पहाड़ी स्थित परसिया गांव में मंडलीय होमगार्ड प्रशिक्षण केंद्र व कार्यालय का शिलान्यास करने मीरजापुर आए थे। शिलान्यास के उपरांत 'हिन्दुस्थान समाचार' से राज्यमंत्री धर्मवीर प्रजापति ने कहा कि वर्ष 2017 से पहले होमगार्ड विभाग बदहाल स्थिति में था। जवानों को न पर्याप्त सुविधाएं मिलती थीं और न ही उनके भविष्य की कोई चिंता की जाती थी। आज प्रदेश सरकार होमगार्ड विभाग को मजबूत करने के लिए लगातार ऐतिहासिक फैसले ले रही है। वर्ष 1962 के बाद पहली बार 41,426 जवानों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई, जो यह साबित करता है कि सरकार युवाओं और सुरक्षा व्यवस्था दोनों को मजबूत करने के लिए गंभीर है।

मंत्री ने कहा कि पहले ड्यूटी के दौरान किसी जवान की मृत्यु होने पर परिवार को मात्र तीन लाख रुपये की सहायता मिलती थी, लेकिन वर्तमान सरकार ने इसे बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दिया। साथ ही बैंकों से समझौता कर अतिरिक्त 35 लाख रुपये की सहायता सुनिश्चित की गई है। अब किसी हादसे की स्थिति में जवान के परिवार को कुल 40 लाख रुपये तक की आर्थिक मदद मिल रही है। उन्होंने कहा कि विपक्ष केवल बयानबाजी करता रहा, जबकि हमारी सरकार जमीन पर काम कर रही है। जिन जिलों में होमगार्ड मुख्यालय नहीं थे वहां भवन बन रहे हैं, मंडलीय कार्यालय तैयार किए जा रहे हैं और जवानों के लिए आधुनिक आवासीय सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। दैनिक भत्ता और प्रशिक्षण भत्ता भी समान कर दिया गया है, ताकि जवानों का मनोबल बढ़े।

पौधरोपण और जल संरक्षण को बनाएं जनआंदोलन धर्मवीर प्रजापति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार विकास और पर्यावरण संरक्षण दोनों पर समान रूप से काम कर रही है।

उन्होंने लोगों से पौधरोपण और जल संरक्षण को जनआंदोलन बनाने की अपील करते हुए कहा कि आने वाली पीढ़ियों को शुद्ध हवा और पानी देना हम सबकी जिम्मेदारी है। मीरजापुर, सोनभद्र व भदोही के जवानों को मिलेगा आधुनिक प्रशिक्षण राज्यमंत्री धर्मवीर ने कहा कि नए प्रशिक्षण केंद्र के निर्माण से विंध्याचल मंडल के मीरजापुर, सोनभद्र और भदोही के होमगार्ड जवानों को आधुनिक सुविधाओं से युक्त प्रशिक्षण मिल सकेगा।

इससे जवानों की कार्यक्षमता बढ़ेगी और आपदा प्रबंधन व सुरक्षा व्यवस्था में उनकी भूमिका और मजबूत होगी। उन्होंने बताया कि अब तक जवानों को प्रशिक्षण के लिए दूसरे जनपदों में जाना पड़ता था, जिससे समय और संसाधनों की दिक्कत होती थी। परसिया गांव में प्रशिक्षण केंद्र बनने से स्थानीय स्तर पर ही बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

आईजीआरएस की बैठक में डीएम ने कसे अधिकारियों के पेंच

फर्रूखाबाद। जिलाधिकारी डॉ. अंकुर लाठर ने आईजीआरएस की बैठक में अधिकारियों के पेंच कसे। उन्हें निर्देश दिया कि शिकायतों का निस्तारण कागजों पर नहीं, शिकायतकर्ता से रूबरू होकर किया जाए।

कलेक्ट्रेट सभागार, फतेहगढ़ में शिकायतों के निस्तारण एवं उनकी गुणवत्ता की समीक्षा हेतु महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा शिकायतों के निस्तारण की स्थिति, शिकायतकर्ताओं से संवाद, साक्ष्यों के अपलोड तथा फीडबैक की गुणवत्ता की गहन समीक्षा की गई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी सक्षम अधिकारी स्वयं निस्तारण आख्या का परीक्षण कर उसे पोर्टल पर अपलोड कराया जाना सुनिश्चित करें। केवल औपचारिक निस्तारण पर्याप्त नहीं है, बल्कि प्रत्येक शिकायत का गुणवत्तापूर्ण एवं तथ्यपरक समाधान किया जाना आवश्यक है। उन्होंने निर्देशित किया कि प्रत्येक निस्तारण आख्या के साथ आवश्यक साक्ष्य अनिवार्य रूप से संलग्न किए जाएं, जिनमें शिकायतकर्ता से वार्ता, स्थलीय निरीक्षण की रिपोर्ट तथा शिकायतकर्ता की अनुपस्थिति में दो पड़ोसियों के बयान सम्मिलित हों। जिलाधिकारी ने शिकायतकर्ताओं से संपर्क न करने वाले अधिकारियों पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि शिकायतकर्ता से संवाद स्थापित न करना गंभीर लापरवाही एवं अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक शिकायतकर्ता से व्यक्तिगत रूप से वार्ता कर उसकी समस्या को समझते हुए गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।

जिलाधिकारी ने चेतावनी दी कि भविष्य में यदि किसी अधिकारी द्वारा गुणवत्ताहीन अथवा तथ्यहीन निस्तारण किया जाता है तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध प्रतिकूल प्रविष्टि सहित कठोर प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने पिछले एक माह में प्राप्त असंतोषजनक फीडबैक वाले संदर्भों को चिन्हित करते हुए निर्देश दिए कि ऐसे प्रकरणों की पुनः जांच कर गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कराया जाए। राजस्व विभाग से संबंधित शिकायतों के पुनरीक्षण हेतु अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) तथा अन्य विभागीय शिकायतों हेतु मुख्य विकास अधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी गई। जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिए कि सभी अधिकारी प्रतिदिन कार्यालय पहुंचने के उपरांत सर्वप्रथम IGRS पोर्टल का अवलोकन करें तथा लंबित शिकायतों की समीक्षा कर उनका निस्तारण स्वयं की निगरानी में सुनिश्चित करें।

दिबियापुर में इलेक्ट्रॉनिक्स की थोक दुकान में भीषण आग, 30 लाख का सामान राख

औरैया। उत्तर प्रदेश के औरैया जनपद के दिबियापुर स्थित स्टेशन रोड पर शुक्रवार को तड़के अभिषेक इलेक्ट्रॉनिक्स की थोक दुकान में भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आकर एलईडी, वायर, एमसीबी और इलेक्ट्रिक पैनल सहित करीब 30 लाख रुपये से अधिक का सामान जलकर राख हो गया। दुकान मालिक अभिषेक शर्मा के अनुसार दुकान में बिजली फिटिंग का थोक कारोबार होता था। शुक्रवार सुबह करीब 3 बजे स्थानीय लोगों ने दुकान के शटर से धुआं निकलता देखा और तुरंत फायर स्टेशन को सूचना दी। मौके पर पहुंची दमकल की दो गाड़ियों ने करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। घटना के समय दुकान बंद होने से कोई जनहानि नहीं हुई। घटना के बाद व्यापार मंडल के पदाधिकारी मौके पर पहुंचे और प्रशासन से पीड़ित व्यापारी को मुआवजा देने की मांग की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीएफओ वीर सिंह ने बताया कि कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया लिया गया था।

भारत-नेपाल सीमा की ककरहवा चेक पोस्ट पर लगे सीसीटीवी कैमरे

सिद्धार्थनगर। भारत -नेपाल सीमा पर जनपद सिद्धार्थनगर के ककरहवा चेक पोस्ट पर क्रिटिकल गैप्स योजना के तहत जिला प्रशासन द्वारा शुक्रवार को कुल 23 सीसीटीवी कैमरे लगवाए गये। इसका शुभारंभ सिद्धार्थनगर के जिलाधिकारी शिवशनरप्पा जी एन ने किया।

इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि यह कैमरे अंतरराष्ट्रीय सीमा क्षेत्र के प्रमुख मार्गों, संवेदनशील तिराहों के अलावा आवागमन वाले बिंदुओं पर लगवाये गये हैं। इन पर निगरानी के लिए सातों दिन 24 घण्टे कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है। इस हाईटेक सेक्युरिटी व्यवस्था से तस्करी, अवैध घुसपैठ, मादक पदार्थों की तस्करी एवं अन्य सीमापार अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने में सहायता मिलेगी जबकि 43 वीं सीमा सशस्त्र बल के कमाडेंट उज्जवल दत्ता ने कहा कि सीमा पर ककरहवा पोस्ट पर सीटीवी कैमरे लगने से भारत-नेपाल सीमा पर अवैध गतिविधियों पर। अंकुश लगाने में बहुत मदद मिलेगी।

समाजवादी पार्टी ने महंगाई के खिलाफ किया प्रदर्शन

देवरिया। उत्तर प्रदेश के जनपद देवरिया में बरहज नगर में शुक्रवार को काली मंदिर के पास सपा कार्यकर्ताओं ने कामर्शियल गैस सिलेंडर का मूल्य बढ़ाये जाने के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने प्रदर्शन किया।

इस अवसर पर सपा नेता विजय रावत ने कहा की उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार में महंगाई चरम पर है। इस दौरान अमित प्रधान, विकास कुमार, राहुल सिंह, संजय तिवारी, राजू मिश्रा, अजय गुप्ता, विमलेश तिवारी, राकेश सिंह, संजय चौहान, अखिलेश कुमार, महावीर प्रसाद, आदित्य यादव, विरेंद्र कुमार, अखिलेश मिश्रा इत्यादि लोग मौजूद रहे।

मजबूत बूथ ही दिलाएगा मिशन-2027 में प्रचंड जीत : विजय रघुवंशी

सुलतानपुर। उत्तर प्रदेश के जिला सुलतानपुर मे भाजपा ने मिशन-2027 की तैयारियों को तेज करते हुए 26 मण्डलों में बैठक कर बूथ स्तर तक संगठन को धार देने का अभियान शुरू कर दिया है। इसी क्रम में इसौली विधानसभा के धम्मौर मण्डल की मासिक एवं कामकाजी बैठक ग्राम पिकौरा स्थित एक निजी विद्यालय परिसर में शुक्रवार को मण्डल अध्यक्ष राम जतन यादव की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।

बैठक में मुख्य अतिथि भाजपा जिला मीडिया प्रमुख एवं मण्डल प्रभारी विजय रघुवंशी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा की ताकत उसका बूथ स्तर तक सक्रिय संगठन और समर्पित कार्यकर्ता हैं। उन्होंने कहा कि मिशन- 2027 में प्रचंड विजय का रास्ता बूथ से होकर गुजरता है। इसलिए प्रत्येक कार्यकर्ता को बूथों पर जनसंपर्क,संवाद और संगठन विस्तार के अभियान में पूरी ताकत से जुटना होगा। बैठक का संचालन मण्डल महामंत्री गणेश शंकर पाण्डेय ने किया।इस अवसर पर पूर्व जिला मंत्री महेश सिंह, पूर्व मण्डल अध्यक्ष नन्दलाल पाल, राम प्रकाश वर्मा, हेमंत तिवारी, राहुल सिंह, कृष्ण कुमार उपाध्याय, राम कुमार मौर्य, संजीव तिवारी, मण्डल मीडिया प्रभारी जेपी मिश्रा सहित कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इसी क्रम में लोहरामऊ मण्डल में जिला महामंत्री विजय त्रिपाठी, मोतिगरपुर मनोज मौर्य, कुड़वार में जिला कोषाध्यक्ष पूजा कसौधन, अयोध्या प्रसाद वर्मा नगर मण्डल, रामेन्द्र प्रताप सिंह करौंदीकला, राजेश सिंह गोसैसिंहपुर, आशीष सिंह रानू पीपरगांव, मनोज श्रीवास्तव लंभुआ मण्डल बैठक में शामिल हुए।

राजस्थान रॉयल्स से आगे निकलने की कोशिश करेगा गुजरात टाइटंस

जयपुर। आत्मविश्वास से ओतप्रोत गुजरात टाइटन्स शनिवार को यहां राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ होने वाले इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के मैच में अपनी जीत का सिलसिला जारी रखकर अंक तालिका में अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश करेगा। राजस्थान रॉयल्स और गुजरात की टीम की स्थिति लगभग समान है। इन दोनों ने अब तक 10 मैचों में छह जीत और चार हार दर्ज की हैं। रॉयल्स बेहतर नेट रन रेट (0.510) के कारण गुजरात से आगे है। गुजरात टाइटन्स ने हालांकि लगातार तीन जीत हासिल की हैं और वह शीर्ष चार में जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। रॉयल्स को अपने पिछले पांच मैचों में से तीन मैच में हार का सामना करना पड़ा है। रॉयल्स ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ अपने पिछले मैच में कप्तान रियान पराग के 90 रन की मदद से छह विकेट पर 225 रन बनाए थे लेकिन उसके गेंदबाज इस स्कोर का बचाव नहीं कर पाए थे। यह लगातार दूसरा मौका था जब रॉयल्स 220 से अधिक के स्कोर का बचाव नहीं कर पाया। राजस्थान रॉयल्स हालांकि वैभव सूर्यवंशी

(404 रन), यशस्वी जायसवाल (312) और यहां तक कि ध्रुव जुरेल (290) जैसे शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों के कारण काफी मजबूत है, लेकिन उसका मध्य और निचले क्रम के बल्लेबाज अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं। इन बल्लेबाजों में केवल डोनोवन फरेरा (229) ही 150 या उससे अधिक रन बना पाए हैं। जुरेल रॉयल्स की बल्लेबाजी का महत्वपूर्ण अंग है लेकिन वह अपेक्षित तेजी से रन नहीं बन पा रहे हैं। जुरेल ने अपनी पिछली तीन पारियों में तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए 30 गेंदों में 42 रन, 20 गेंदों में 16 रन और 30 गेंदों में 42 रन बनाए हैं। इन आंकड़ों को देखकर स्पष्ट हो जाता है कि सुधार की गुंजाइश है क्योंकि टूर्नामेंट में यह साफ हो गया कि कोई भी स्कोर सुरक्षित नहीं है। आईपीएल का मौजूदा सत्र गेंदबाजों के लिए अच्छा नहीं रहा है और ऐसे में रॉयल्स को विशेष कर बीच के ओवरों में अपनी गेंदबाजी की समस्याओं को दूर करना होगा। गुजरात टाइटंस की टीम इस बात से खुश होगी कि उसने सही समय पर लय हासिल कर ली है। कप्तान शुभमन गिल (378 रन) के प्रदर्शन में निरंतरता है और वह इसे बरकरार रखने के लिए प्रतिबद्ध होंगे। साई सुदर्शन (385) भी अपनी फॉर्म का पूरा फायदा उठाना चाहेंगे। उन्होंने अपनी पिछली चार पारियों में दो अर्धशतक और एक शतक लगाया है। जोस बटलर (335) के निरंतरता बनाए रखने से गुजरात टाइटन्स का शीर्ष क्रम बेहद मजबूत नजर आता है। उसके पास निचले क्रम में मुश्किल परिस्थितियों से निपटने में माहिर अच्छे फिनिशर भी हैं। गुजरात टाइटंस की गेंदबाजी भी अच्छी है। कैगिसो रबाडा (16 विकेट) तेज गेंदबाजी आक्रमण की अगुवाई बखूबी कर रहे हैं। उसकी टीम रबाडा, प्रसिद्ध कृष्णा (12) और मोहम्मद सिराज (11) की तेज गेंदबाजी तिकड़ी के प्रदर्शन से काफी खुश होगी। यहां सवाई मानसिंह स्टेडियम में 220 से अधिक के स्कोर का दो बार सफलतापूर्वक पीछा किया जा चुका है, इसलिए टॉस जीतने वाली टीम पहले फील्डिंग करना पसंद करेंगी।

इस प्रकार हैं टीम

राजस्थान रॉयल्स: रियान पराग (कप्तान), अमन राव, शुभम दुबे, शिमरोन हेटमायर, यशस्वी जयसवाल, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), वैभव सूर्यवंशी, लुआन-ड्रे प्रिटोरियस, रवि सिंह, डोनोवन फरेरा, रवींद्र जडेजा, दासुन शनाका, जोफ्रा आर्चर, ब्रिजेश शर्मा, नांद्रे बर्गर, तुषार देशपांडे, क्वेना मफाका, एडम मिल्ने, सुशांत मिश्रा, विग्नेश पुथुर, रवि बिश्नोई, संदीप शर्मा, कुलदीप सेन, यशराज पुंजा, युद्धवीर सिंह।

गुजरात टाइटंस: शुभमन गिल (कप्तान), अनुज रावत, जोस बटलर (विकेटकीपर), कॉनर एस्टरहुइजन, कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), बी साई सुदर्शन, एम शाहरुख खान, जेसन होल्डर, ग्लेन फिलिप्स, राशिद खान, निशांत सिद्धू, मानव सुथार, राहुल तेवतिया, वाशिंगटन सुंदर, अरशद खान, अशोक शर्मा, गुरनूर बराड़, कुलवंत खेजरोलिया, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, कैगिसो रबाडा, आर साई किशोर, ईशांत शर्मा, ल्यूक वुड, जयंत यादव।

मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे शुरू होगा।

कोहली का विकेट लेने से अच्छा लगा, लेकिन मैच जीतना महत्वपूर्ण: प्रिंस यादव

लखनऊ। लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) के तेज गेंदबाज प्रिंस यादव ने यहां आईपीएल मैच के दौरान रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली को एक बेहतरीन गेंद से आउट किया, लेकिन वह इसे ज्यादा तवज्जो नहीं देना चाहते और उन्होंने कहा कि टीम का जीत हासिल करना अधिक महत्वपूर्ण है। आरसीबी की टीम बारिश से प्रभावित इस मैच में डकवर्थ लुईस पद्धति से 213 रन के लक्ष्य का पीछा कर रही थी लेकिन उसकी टीम निर्धारित 19 ओवर में छह विकेट पर 203 रन ही बना पाई। मिचेल मार्श के 111 रन की बदौलत एलएसजी ने तीन विकेट पर 209 रन बनाए थे। प्रिंस ने 33 रन देकर तीन विकेट लिए। प्रिंस ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ''कोहली का विकेट लेने के बाद मुझे अच्छा लगा, लेकिन सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि हमने मैच जीत लिया। अगर मैंने विकेट लिया होता और हम हार जाते, तो इतना अच्छा नहीं लगता।'' उन्होंने कहा, ''कोई भी गेंदबाज जब किसी भी तरीके से विकेट लेता है तो अच्छा लगता है। अगर परिस्थिति ऐसी होती है कि हम विकेट लेकर ही मैच जीत सकते हैं तो वही हुआ और मुझे अच्छा लग रहा है।'' प्रिंस ने इस सत्र में शानदार प्रदर्शन करते हुए 16 विकेट लिए हैं, जो शीर्ष पर चल रहे गेंदबाजों भुवनेश्वर कुमार (17) और अंशुल कंबोज (17) से केवल एक विकेट कम है। इस 24 वर्षीय खिलाड़ी ने कहा कि उन्होंने सीनियर तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी से नई गेंद से गेंदबाजी करने के बारे में बहुत कुछ सीखा है। उन्होंने कहा, ''मैंने उनसे (शमी से) नई गेंद से गेंदबाजी करने के बारे में बहुत कुछ सीखा। उनकी सबसे अच्छी बात यह है कि जब भी कोई गेंदबाज गेंदबाजी कर रहा होता है तो वह मिड-ऑन या मिड-ऑफ पर खड़े होते हैं। अगर आपका साथ देने के लिए इतना अनुभवी खिलाड़ी हो तो आत्मविश्वास का स्तर अलग हो जाता है।'' आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने स्वीकार किया कि प्रिंस की गेंदबाजी ने मैच का रुख बदल दिया। पाटीदार ने कहा, ''हमने दिल्ली में प्रिंस के साथ कई घरेलू मैच खेले हैं। मैं उन्हें लंबे समय से देखता आ रहा हूं। उनकी गेंदबाजी में विविधता है। उनके पास गति है। उनके पास स्विंग है। वह एक कुशल तेज गेंदबाज हैं। उन्होंने आज बहुत अच्छी गेंदबाजी की। मुझे लगता है कि अपनी गेंदबाजी से उन्होंने मैच का रुख बदल दिया।'' आरसीबी अभी 10 मैचों के बाद 12 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर है और पाटीदार ने कहा कि उनकी टीम खिताब का बचाव कर सकती है। उन्होंने कहा, ''हम इस सत्र में मौजूदा चैंपियन के रूप में खेल रहे हैं और हमारे पास फिर से चैंपियन बनने का मौका है।

खिलाड़ियों के कमरों में अनधिकृत प्रवेश पर रोक, बीसीसीआई ने हनी ट्रैप, सुरक्षा जोखिम के प्रति चेताया

नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने संभावित 'हनी ट्रैप, कानूनी दायित्व और सुरक्षा जोखिमों' के प्रति आगाह करते हुए इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में खिलाड़ियों, सहयोगी स्टाफ के सदस्यों और टीम अधिकारियों के होटल के कमरों में अनधिकृत लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि बोर्ड की भ्रष्टाचार विरोधी इकाई (एसीयू) ने 'दुर्व्यवहार और प्रोटोकॉल के उल्लंघन' की घटनाओं को उजागर किया था।

बीसीसीआई ने आईपीएल की 10 फ्रेंचाइजी के लिए जारी एक पत्र में कहा है कि खिलाड़ियों और अधिकारियों के कमरों में मेहमानों के प्रवेश के लिए टीम मैनेजरों से लिखित अनुमति लेना अनिवार्य होगी। बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने 10 फ्रेंचाइजी के सीईओ को जो पत्र लिखा है, उसकी एक प्रति पीटीआई के पास है। सैकिया ने पत्र में कहा है, ''मौजूदा सत्र के दौरान कुछ घटनाओं को देखते हुए यह सलाह जारी की गई है और इसका उद्देश्य आईपीएल से जुड़े सभी हितधारकों से अपेक्षित पेशेवरपन, अनुशासन, सुरक्षा जागरूकता और प्रोटोकॉल का पालन करने के मानकों को मजबूत करना है।'' बीसीसीआई के संज्ञान में आया है कि आईपीएल के मौजूदा सत्र के दौरान खिलाड़ियों, सहयोगी स्टाफ के सदस्यों और टीम अधिकारियों से जुड़े दुर्व्यवहार और प्रोटोकॉल उल्लंघन की कुछ घटनाएं हुई हैं। सैकिया ने पत्र की प्रस्तावना में कहा, ''यदि इन घटनाओं पर ध्यान नहीं दिया गया, तो टूर्नामेंट, संबंधित फ्रेंचाइजी और

शासी निकाय के रूप में बीसीसीआई की प्रतिष्ठा को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है। इससे व्यक्तियों और फ्रेंचाइजी को गंभीर कानूनी दायित्व और सुरक्षा जोखिमों का सामना करना पड़ सकता है।'' बीसीसीआई ने कहा कि यह देखा गया है कि कुछ खिलाड़ियों और सहयोगी स्टाफ के सदस्यों ने संबंधित आईपीएल फ्रेंचाइजी टीम के मैनेजर की जानकारी या अनुमति के बिना अनधिकृत व्यक्तियों को होटल के अपने कमरों में प्रवेश करने की अनुमति दी है।'' पत्र में कहा गया हे, ''कई मामलों में टीम मैनेजर को ऐसे मेहमानों की उपस्थिति के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था।

इस चलन को तत्काल प्रभाव से सख्ती से प्रतिबंधित किया जाता है।'' सभी खिलाड़ियों और सहयोगी स्टाफ के सदस्यों को अब एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) दी गई है जिसका पालन टूर्नामेंट की पूरी अवधि के दौरान करना आवश्यक होगा। इसमें कहा गया है, ''टीम मैनेजर की पूर्व सूचना और स्पष्ट लिखित स्वीकृति के बिना खिलाड़ी या सहायक स्टाफ सदस्य के होटल के कमरे में किसी अन्य व्यक्ति को प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।'' पत्र के अनुसार ''बीसीसीआई सभी फ्रेंचाइजी का ध्यान शीर्ष स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में लक्षित यौन शोषण और 'हनी ट्रैपिंग' (सुनियोजित जासूसी या ब्लैकमेलिंग का तरीका, जिसमें किसी व्यक्ति को प्रेम, यौन आकर्षण या भावनात्मक प्रलोभन में फंसाया जाता है) के जोखिमों की तरफ आकर्षित करता है।''

बोर्ड ने कहा, ''ऐसी घटनाओं की संभावना को नकारा नहीं जा सकता जिनसे गंभीर कानूनी आरोप लग सकते हैं, जिनमें यौन दुर्व्यवहार से संबंधित लागू भारतीय कानूनों के तहत आरोप भी शामिल हैं। आईपीएल फ्रेंचाइजी को ऐसे जोखिमों को कम करने के लिए हर समय सतर्क और सक्रिय रहना चाहिए।'' इसमें खिलाड़ियों और सहयोगी स्टाफ के सदस्यों को अपने नामित सुरक्षा अधिकारी (एसएलओ) और टीम इंटीग्रिटी अधिकारी (टीआईओ) को सूचित किए बिना 'अनियमित समय' पर टीम के होटलों से बाहर निकलने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। सैकिया ने कहा कि बीसीसीआई या आईपीएल संचालन परिषद दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर जांच कर सकते हैं और उल्लंघन करने पर संबंधित खिलाड़ी, सहायक स्टाफ और टीम अधिकारी पर वित्तीय दंड से लेकर निलंबन या अयोग्यता तक के प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।

ग्लोबल शतरंज लीग का चौथा सत्र भारत में होगा

नई दिल्ली। टेक महिंद्रा और फिडे की संयुक्त पहल ग्लोबल शतरंज लीग का चौथा सत्र भारत में आयोजित किया जाएगा। टूर्नामेंट के आयोजकों ने शुक्रवार को यह घोषणा करते हुए कहा कि उनका उद्देश्य देश में लोकप्रिय हो रही शतरंज संस्कृति का लाभ उठाना है। जीसीएल ने कहा कि मेजबान शहर की घोषणा जल्द की जाएगी। इस आयोजन का तीसरा सत्र पिछले दिसंबर में मुंबई में आयोजित किया गया था, जिसमें एल्पाइन एसजी पाइपर्स टीम चैंपियन बनी थी। लीग ने खेल के प्रारूप में बदलाव किया है। रैपिड प्रारूप के मुकाबलों, मिश्रित टीमों और कड़े प्रतिस्पर्धी मैचों के जरिए इसे दर्शकों के लिए अधिक आकर्षक बनाने की कोशिश की जा रही है। ग्लोबल शतरंज लीग के आयुक्त गौरव रक्षित ने कहा, ''खेल के प्रति भारत का जुनून और इसका तेजी से बढ़ता शतरंज पारिस्थितिकी तंत्र इसे लीग के लिए एक स्वाभाविक गंतव्य बनाता है। हम एक और रोमांचक सत्र का इंतजार कर रहे हैं, जो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों और वैश्विक प्रशंसक वर्ग को एक साथ लाएगा।'' चौथा सत्र एक बार फिर टीम-आधारित प्रारूप में दुनिया के अग्रणी खिलाड़ियों को एक साथ लाएगा।

पैसे या भव्य परेड नहीं, बस चाहता हूं कि सभी खेलों की सफलता का जश्न मनेः सात्विक

नई दिल्ली। स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी ने शुक्रवार को कहा कि थॉमस कप में भारतीय टीम द्वारा कांस्य पदक जीतने के बाद जनता की फीकी प्रतिक्रिया पर की गई उनकी हालिया टिप्पणी का उद्देश्य 'पैसे या भव्य स्वागत' की मांग करना नहीं था, बल्कि लोगों से सभी खेलों में 'हर छोटी-बड़ी जीत का जश्न मनाने' की अपील करना था। विश्व रैंकिंग में चौथे स्थान पर काबिज एशियाई खेलों के चैंपियन सात्विक और चिराग शेट्टी की जोड़ी हाल ही में डेनमार्क में आयोजित थॉमस कप में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थी। सात्विक ने हालांकि स्वदेश लौटने पर सोशल मीडिया पर उनकी उपलब्धि को अपेक्षित पहचान न मिलने को लेकर अपनी भावनाएं व्यक्त की थीं। डेनमार्क से वापस आने के बाद सात्विक ने लिखा था, ''अब घर वापस आ गया हूं। हमेशा की तरह, पिछले दो सप्ताहों में क्या हुआ, यह किसी को पता नहीं है और ऐसा लगता है कि किसी को वास्तव में इसकी परवाह भी नहीं है।'' इस 25 साल के खिलाड़ी ने शुक्रवार को अपने विचारों को और स्पष्ट करने के लिए एक और सोशल मीडिया पोस्ट साझा किया। उन्होंने लिखा, ''पिछले कुछ दिनों में थॉमस कप कांस्य पदक को लेकर मेरी टिप्पणियों पर काफी ध्यान दिया गया। मैं लोगों के समर्थन और प्रोत्साहन के लिए आभारी हूं, लेकिन मैं अपने इरादे को स्पष्ट करना चाहता हूं क्योंकि कई लोग मूल मुद्दे से भटकते नजर आ रहे हैं।'' उन्होंने लिखा, ''मेरे शब्द व्यक्तिगत प्रसिद्धि पाने या किसी और की उपलब्धियों का श्रेय कम करने की भावना से नहीं आए थे। मैं हर उस खिलाड़ी का बेहद सम्मान करता हूं जो किसी भी खेल में भारत का नाम रोशन करता है।'' सात्विक ने कहा, ''मेरा संदेश केवल इतना था कि हमें ऐसी संस्कृति विकसित करनी चाहिए, जहां हर छोटी या

बड़ी जीत का उत्साहपूर्वक से जश्न मनाया जाए।'' उन्होंने कहा कि थॉमस कप जैसे टूर्नामेंट में उत्कृष्ट प्रदर्शन खिलाड़ियों के वर्षों के त्याग और कठिन मेहनत का परिणाम होता है और जब ऐसी उपलब्धियों पर 'चुप्पी छा जाती' है तो यह 'बेहद निराशाजनक' लगता है। उन्होंने लिखा, ''चाहे वह विश्व कप का पदक हो या थॉमस कप जैसे वैश्विक टूर्नामेंट में पोडियम फिनिश, ये पल वर्षों की मेहनत और बलिदान का प्रतिनिधित्व करते हैं।'' इस खिलाड़ी ने कहा, ''जब ऐसी उपलब्धियों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती, तो यह सिर्फ हमारे लिए ही नहीं बल्कि भविष्य के खिलाड़ियों के लिए भी निराशाजनक होता है, जो हमें देखकर प्रेरणा लेते हैं।'' सात्विक ने कहा, ''हमें न पैसे चाहिए, न भव्य परेड; हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमारा देश हमें देखे और हमारे प्रयासों को महसूस करे। चलिए हम सभी खेलों को समान उत्साह और जुनून के साथ समर्थन दें।' उनकी भावनाओं का समर्थन उनके जोड़ीदार चिराग ने भी किया। चिराग ने देश के खेल प्रेमियों से अपील की कि वे हर उस खिलाड़ी का सम्मान करें जो भारत की जर्सी पहनकर देश का प्रतिनिधित्व करता है।

डिजिटल सेवाओं तक पहुंच और साइबर सुरक्षा बड़ी चुनौतीः नागेश्वरन

नई दिल्ली। मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) वी. अनंत नागेश्वरन ने शुक्रवार को कहा कि भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) ने वैश्विक स्तर का विस्तार हासिल किया है लेकिन डिजिटल पहुंच, पारस्परिक संचालन क्षमता एवं साइबर सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियां अब भी चिंता का विषय हैं। भारतीय अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान (आईसीआरआईईआर) परिषद द्वारा 'डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना एवं सार्वजनिक सेवा वितरण' विषय पर आयोजित कार्यक्रम में नागेश्वरन ने कहा कि आबादी का बड़ा हिस्सा, खासकर बुजुर्ग, कमजोर संपर्क वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और कम साक्षरता या सीमित डिजिटल समझ रखने वालों को अब भी डिजिटल सेवाओं तक पहुंच कायम करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

उन्होंने कहा, '' डिजिटल अवसंरचना चाहे जितनी उन्नत हो, वह पूर्ण अर्थों में डिजिटल समावेशन के बराबर नहीं है। सबसे अधिक जरूरतमंद लोगों तक डिजिटल माध्यम से आसानी से सेवाएं पहुंचाने के लिए अब भी प्रयास किए जा रहे हैं।'' नागेश्वरन ने कहा कि डेटा साझा करने और डिजिटल अभिलेख के क्षेत्र में विधायी एवं संस्थागत ढांचा अभी विकसित हो रहा है। राज्यों के बीच डीपीआई की पारस्परिक संचालन क्षमता अब भी प्रगति पर है। केंद्र सरकार की प्रणालियां अपेक्षाकृत बेहतर ढंग से एकीकृत हो रही हैं। हालांकि राज्यों के स्तर पर डिजिटल अवसंरचना की गुणवत्ता और पूर्णता में अब भी काफी अंतर है।'' साइबर सुरक्षा के बारे में उन्होंने कहा कि खतरों की जटिलता लगातार बढ़ने के मद्देनजर इस क्षेत्र में निरंतर ध्यान देने की जरूरत है।

शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन गिरावट, सेंसेक्स 516 अंक फिसला

मुंबई। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच निवेशकों की धारणा कमजोर पड़ने से घरेलू शेयर बाजारों में शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन गिरावट रही। सेंसेक्स करीब 516 अंक टूटकर बंद हुआ जबकि निफ्टी में 150 अंक की गिरावट आई। विश्लेषकों के मुताबिक, ऊर्जा आपूर्ति को लेकर चिंताएं बढ़ने से बाजार में जोखिम से बचने का रुझान देखा गया।

विदेशी निवेशकों की बिकवाली और वैश्विक बाजारों के कमजोर रुख ने भी गिरावट को बढ़ाया। बीएसई का 30 शेयरों पर आधारित मानक सूचकांक सेंसेक्स 516.33 अंक यानी 0.66 प्रतिशत गिरकर 77,328.19 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय यह 698.09 अंक तक लुढ़क गया था। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का मानक सूचकांक निफ्टी 150.50 अंक यानी 0.62 प्रतिशत गिरकर 24,176.15 अंक पर आ गया। साप्ताहिक आधार पर बीएसई सेंसेक्स में 414.69 अंक यानी 0.53 प्रतिशत की बढ़त रही जबकि एनएसई निफ्टी में 178.6 अंक यानी 0.74 प्रतिशत की तेजी रही। सेंसेक्स के समूह में शामिल कंपनियों में से भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के शेयर में मार्च तिमाही नतीजों के बाद 6.62 प्रतिशत की गिरावट आई।

इसके अलावा एचडीएफसी बैंक, बजाज फाइनेंस, एक्सिस बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट और महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर भी नुकसान में रहे। हालांकि, टाइटन के शेयर अनुकूल तिमाही नतीजों के बाद 4.76 प्रतिशत चढ़ गया। इसके साथ एशियन पेंट्स, अदाणी पोर्ट्स, इन्फोसिस और एचसीएल टेक के शेयरों में भी तेजी रही। रेलिगेयर ब्रोकिंग लिमिटेड के वरिष्ठ उपाध्यक्ष (शोध) अजीत मिश्रा ने कहा, ₹कमजोर वैश्विक संकेतों और नई भू-राजनीतिक चिंताओं के बीच घरेलू बाजार दबाव में रहे। कच्चे तेल में फिर से तेजी आने से निवेशक धारणा बिगड़ गई। इसके अलावा रुपये में कमजोरी कायम रहने और संस्थागत निवेशकों के रुख से भी प्रभाव पड़ा।

व्यापक बाजार में छोटी कंपनियों का बीएसई स्मालकैप सेलेक्ट सूचकांक 0.34 प्रतिशत के नुकसान में रहा जबकि मझोली कंपनियों के मिडकैप सेलेक्ट सूचकांक में 0.01 प्रतिशत की मामूली गिरावट रही। वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड करीब 100 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा, ₹अमेरिका -ईरान के बीच ताजा सैन्य कार्रवाई से संघर्षविराम की उम्मीदें कमजोर पड़ीं, जिससे निवेशकों ने मुनाफावसूली की और जोखिम से बचने की कोशिश की।

सिंगापुर ने 2025 में 1.69 करोड़ पर्यटकों से 32.8 अरब सिंगापुर डॉलर कमाए

सिंगापुर। सिंगापुर ने वर्ष 2025 में 1.69 करोड़ पर्यटकों से रिकॉर्ड 32.8 अरब सिंगापुर डॉलर (25.9 अरब अमेरिकी डॉलर) की आय अर्जित की। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। व्यापार संबंधों की प्रभारी मंत्री ग्रेस फू ने अगले पांच वर्ष में पर्यटन विकास कोष के लिए अतिरिक्त 74 करोड़ सिंगापुर डॉलर की वित्तीय सहायता की घोषणा की। यह 2024 में दिए गए 30 करोड़ सिंगापुर डॉलर से अधिक है। फू ने पर्यटन उद्योग सम्मेलन में कहा, '' 2025 में हमारा मजबूत प्रदर्शन उत्साहजनक है, लेकिन हम इससे संतुष्ट नहीं हो सकते। पश्चिम एशिया ऊर्जा संकट और इसके उपभोक्ता खर्च पर प्रभाव के कारण आगे चुनौतियां बनी हुई हैं।'' उन्होंने कहा, '' यह वित्तीय सहायता 'टूरिज्म 2040' के तहत हमारी महत्वाकांक्षाओं को समर्थन देगी जिससे विकास के अगले चरण को दिशा मिलेगी एवं सिंगापुर को एक आकर्षक पर्यटन गंतव्य बनाए रखा जा सकेगा।'' इस कोष से पांच लाख सिंगापुर डॉलर का अनुदान व्यवसायों को विपणन गतिविधियां बढ़ाने और सिंगापुर में व्यावसायिक आयोजनों में भागीदारी बढ़ाने के लिए दिया जाएगा। इसके अलावा पांच लाख सिंगापुर डॉलर एक 'मार्केट एक्सेस फंड' के लिए निर्धारित किए जाएंगे जिससे कंपनियों को नए बाजारों में अपनी उपस्थिति बढ़ाने में मदद मिलेगी। 'टूरिज्म 2040' योजना के तहत सिंगापुर पर्यटन बोर्ड का अनुमान है कि 2040 तक पर्यटन आय 47 अरब से 50 अरब सिंगापुर डॉलर के बीच पहुंच जाएगी। सिंगापुर पर्यटन बोर्ड के अनुसार, 2026 में पर्यटन आय 31 अरब से 32.5 अरब सिंगापुर डॉलर के बीच और अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या 1.7 करोड़ से 1.8 करोड़ के बीच रहने का अनुमान है। वर्ष 2024 में सिंगापुर ने 1.65 करोड़ पर्यटकों से 29.8 अरब सिंगापुर डॉलर की आय अर्जित की थी। खबरों के अनुसार, 2025 में सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे ने लगभग सात करोड़ यात्रियों की आवाजाही दर्ज की। सिंगापुर पर्यटन बोर्ड की मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) मेलिसा आउ ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं और पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण आने वाले महीनों में मांग पर दबाव रह सकता है। उन्होंने कहा, '' हमारे पर्यटन व्यवसाय इस संकट और वैश्विक अनिश्चितता के कारण दबाव में हैं। हालांकि पहली तिमाही में पर्यटकों की संख्या में सालाना आधार पर तीन प्रतिशत वृद्धि हुई लेकिन आगे मांग नरम पड़ सकती है।

बिहार में कीट हमले से लीची की फसलों का हुए नुकसान का आकलन करेगा कार्यबलः केंद्र

नई दिल्ली। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र सरकार ने बिहार में कीट हमले से लीची की फसलों को हुए नुकसान का आकलन करने के लिए विशेषज्ञों का एक कार्यबल गठित किया है। यह कार्यबल बिहार के लीची किसानों की शिकायतों के बाद गठित किया गया है। शिकायतों

में 'स्टिंक बग' के कारण लीची की फसल को नुकसान होने की बात कही गई है। दल प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेगा, नुकसान की सीमा का आकलन करेगा और किसानों को राहत देने के लिए तात्कालिक एवं दीर्घकालिक उपायों की सिफारिश करेगा। चौहान ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर लिखा, '' दल एक सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट सौंपेगा ताकि समय पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।'' केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कार्यबल राज्य एवं केंद्र दोनों स्तरों पर आवश्यक हस्तक्षेपों के बारे में भी सलाह देगा। सरकार, किसानों के हितों की रक्षा के लिए ''पूरी संवेदनशीलता एवं प्रतिबद्धता'' के साथ काम कर रही है। बिहार भारत का प्रमुख लीची उत्पादक राज्य है।

टाटा पावर,डीजीपीसी ने भूटान में अतिरिक्त 404 मेगावाट जलविद्युत परियोजना करने के लिए बढ़ाया सहयोग

नई दिल्ली/थिम्फू। टाटा पावर और भूटान की ड्रुक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (डीजीपीसी) अपने मौजूदा स्वच्छ ऊर्जा सहयोग के तहत पड़ोसी देश में अतिरिक्त 404 मेगावाट की जलविद्युत परियोजना विकसित करेंगे। मूल समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर 19 नवंबर 2024 को हस्ताक्षर किए गए थे। इसके तहत दोनों पक्षों ने भूटान में कम से कम 4,500 मेगावाट जलविद्युत परियोजनाओं के विकास पर सहयोग करने पर सहमति जताई थी। टाटा पावर ने शुक्रवार को बयान में बताया कि उसने भूटान में अपने स्वच्छ ऊर्जा सहयोग का विस्तार करने के लिए डीजीपीसी के साथ समझौता ज्ञापन में संशोधन पर हस्ताक्षर किए हैं। संशोधन के तहत, 404 मेगावाट की नई न्येरा अमारी I एवं II एकीकृत जलविद्युत परियोजना को मौजूदा परियोजना सूची में जोड़ा गया है। इसके साथ ही साझेदारी के तहत कुल जलविद्युत क्षमता 4,500 मेगावाट से बढ़कर 5,033 मेगावाट हो गई है। यह भूटान के ऊर्जा क्षेत्र के 2040 तक कुल उत्पादन क्षमता 25,000 मेगावाट तक पहुंचाने के लक्ष्य के अनुरूप है। टाटा पावर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) एवं प्रबंध निदेशक प्रवीर सिन्हा ने कहा, '' न्येरा अमारी परियोजना का शामिल होना इस सहयोग के विस्तार, महत्वाकांक्षा और दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह रणनीतिक साझेदारी भूटान की विशाल जलविद्युत क्षमता को उपयोग में लाकर उसकी आर्थिक वृद्धि को गति देने के साथ-साथ क्षेत्रीय ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।'

'दादी की शादी' है दिल के बेहद करीब: सादिया खतीब

मुंबई। अपनी अपकमिंग पारिवारिक ड्रामा फिल्म 'दादी की शादी' को लेकर अभिनेत्री सादिया खतीब चर्चा में हैं। हाल ही में सादिया ने बताया कि इस फिल्म की कहानी उनके दिल को इतनी गहराई से छू गई थी कि उन्होंने इसे साइन करने में बिल्कुल भी समय नहीं लगाया। सादिया के मुताबिक, लंबे समय तक गंभीर और इंटेंस किरदार निभाने के बाद वह कुछ अलग और भावनात्मक कहानी का हिस्सा बनना चाहती थीं। सादिया खतीब ने बताया कि जब उन्होंने पहली बार फिल्म की कहानी सुनी, तो उन्हें तुरंत एहसास हो गया कि यह एक खास प्रोजेक्ट है। उन्होंने कहा कि कहानी सुनने के बाद उन्हें हां करने में मुश्किल से एक मिनट लगा होगा। अभिनेत्री ने बताया कि उन्होंने यह फिल्म अपनी पिछली रिलीज 'डिप्लोमैट' से भी पहले साइन कर ली थी। उनके अनुसार लगातार गंभीर भूमिकाएं निभाने के बाद एक कलाकार के तौर पर बदलाव जरूरी हो जाता है और 'दादी की शादी' उनके लिए वही बदलाव लेकर आई। अभिनेत्री ने कहा कि यह फिल्म सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि परिवार और रिश्तों की भावनात्मक यात्रा है। इसमें माता-पिता, दादा-दादी और परिवार के अन्य सदस्यों के बीच के रिश्तों को बेहद खूबसूरती से दिखाया गया है। उन्होंने कहा कि वह व्यक्तिगत रूप से भी ऐसी कहानी दुनिया के सामने लाना चाहती थीं, जिससे लोग खुद को जोड़ सकें। अपनी निजी जिंदगी का जिक्र करते हुए सादिया खतीब भावुक भी नजर आईं। उन्होंने बताया कि कुछ साल पहले रक्षाबंधन के मौके पर उन्होंने अपनी दादी को खो दिया था और वह उनके बेहद करीब थीं। अभिनेत्री ने कहा कि उनके दादाजी का निधन भी काफी पहले हो गया था। जब उन्होंने फिल्म की स्क्रिप्ट सुनी, तो उन्हें अपनी दादी के साथ बिताए खूबसूरत पल याद आ गए। उन्होंने कहा कि आज भी जब वह अपनी दादी के बारे में सोचती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे वह कल की ही बात हो। सादिया के मुताबिक, फिल्म में उन्हें उसी पवित्र रिश्ते को पर्दे पर निभाने का मौका मिला, जिसने इस प्रोजेक्ट को उनके लिए और भी खास बना दिया। फिल्म के विषय और शीर्षक को लेकर अभिनेत्री का कहना है कि आज के दौर में ऐसी साफ-सुथरी पारिवारिक फिल्में बहुत कम बनती हैं। उन्होंने बताया कि 'दादी की शादी' में कॉमेडी, इमोशन और परिवार से जुड़ी भावनाओं का खूबसूरत मिश्रण देखने को मिलेगा। खास बात यह है कि यह फिल्म हर उम्र के दर्शकों के लिए बनाई गई है और इसे पूरा परिवार साथ बैठकर देख सकता है।

अच्छे कलाकार बनने के लिए धैर्य, मेहनत जरुरी: सई मांजरेकर

मुंबई। अभिनेत्री सई मांजरेकर का मानना है कि एक अच्छे कलाकार बनने के लिए धैर्य, मेहनत और सही प्रोजेक्ट का चुनाव बेहद जरूरी होता है। अभिनेत्री का कहना है कि वह ऐसे काम का हिस्सा बनना चाहती हैं, जो लंबे समय तक दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बनाए रखे। सई मांजरेकर ने हाल ही में मीडिया से अपने करियर और काम करने के तरीके को लेकर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि अब उन्हें यह समझ आ गया है कि एक अभिनेता के रूप में खुद को समय देना बहुत जरूरी है। अभिनेत्री के मुताबिक वह मौजूदा ट्रेंड के पीछे भागने में विश्वास नहीं रखतीं, बल्कि ऐसे प्रोजेक्ट चुनना पसंद करती हैं जो उन्हें एक कलाकार के तौर पर आगे बढ़ने और सीखने का अवसर दें। सई ने कहा कि जब कोई काम पूरी ईमानदारी और दिल से किया जाता है, तो उसका असर दर्शकों पर गहरा पड़ता है और लोग उसे लंबे समय तक याद रखते हैं। उनके अनुसार अभिनय केवल कैमरे के सामने आकर संवाद बोलना नहीं है, बल्कि हर किरदार को महसूस करना और उसमें सच्चाई लाना भी उतना ही जरूरी है। यही वजह है कि वह जल्दबाजी में ज्यादा प्रोजेक्ट साइन करने के बजाय सोच-समझकर काम चुनती हैं। अभिनेत्री ने कहा कि वह अपने हर नए प्रोजेक्ट के साथ खुद को बेहतर बनाना चाहती हैं। उनके लिए यह ज्यादा महत्वपूर्ण है कि वह अपने काम के प्रति ईमानदार रहें और ऐसी कहानियों का हिस्सा बनें, जिनसे वह खुद भी भावनात्मक रूप से जुड़ाव महसूस करें। सई के मुताबिक लंबे समय तक इंडस्ट्री में टिके रहने के लिए कलाकार का अपने काम के प्रति सच्चा होना जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि वह अपने हर किरदार में गहराई और सच्चाई लाने की कोशिश करती हैं ताकि दर्शक उससे खुद को जोड़ सकें। सई का मानना है कि अभिनय में वास्तविक भावनाएं ही किसी किरदार को खास बनाती हैं। इन दिनों सई मांजरेकर अपनी आगामी फिल्म 'इंडिया हाउस' को लेकर चर्चा में हैं। यह फिल्म आजादी से पहले के दौर की कहानी पर आधारित है, जिसमें उस समय के सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं को बड़े स्तर पर दिखाया जाएगा। फिल्म को अभिनेता राम चरण अपने प्रोडक्शन हाउस के जरिए प्रोड्यूस कर रहे हैं और यह उनके प्रोडक्शन करियर का पहला प्रोजेक्ट भी माना जा रहा है।

50 करोड़ क्लब में शामिल हुई 'राजा शिवाजी'

रितेश देशमुख के निर्देशन में बनी ऐतिहासिक फिल्म 'राजा शिवाजी' बॉक्स ऑफिस पर मजबूत पकड़ बनाए हुए है। हिंदी और मराठी में रिलीज हुई इस फिल्म ने रिलीज के सातवें दिन 4 करोड़ रुपये की कमाई करते हुए घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 52.65 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन कर लिया है। फिल्म में छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरगाथा को भव्य अंदाज में पेश किया गया है, जिसे दर्शकों से शानदार प्रतिक्रिया मिल रही है। संजय दत्त, अभिषेक बच्चन, विद्या बालन और जेनेलिया डिसूजा जैसे सितारों से सजी इस फिल्म में सलमान खान का कैमियो भी चर्चा का विषय बना हुआ है। कारोबारी दिनों में भी 'राजा शिवाजी' ने स्थिर प्रदर्शन किया है। फिल्म ने सोमवार को 5.60 करोड़, पांचवें दिन 4.90 करोड़ और छठे दिन 4.25 करोड़ रुपये का कारोबार किया था।

दो बड़ी फिल्मों की रिलीज को लेकर चर्चा तेज

मुंबई। जून महीने में बॉलीवुड दो बड़ी फिल्मों की रिलीज को लेकर चर्चा तेज है। एक तरफ अभिनेत्री जान्हवी कपूर की फिल्म 'पेड्डी' रिलीज होने जा रही है, वहीं दूसरी तरफ अभिनेता वरुण धवन की रोमांटिक-कॉमेडी फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' भी सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है। हालांकि दोनों फिल्मों के बीच संभावित क्लैश को लेकर किसी तरह की प्रतिस्पर्धा नहीं, बल्कि दोस्ताना माहौल देखने को मिल रहा है। जान्हवी कपूर ने सोशल मीडिया पर एक मजेदार वीडियो शेयर कर इस बॉक्स ऑफिस टक्कर को हल्के-फुल्के अंदाज में पेश किया। इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए इस ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो में उन्होंने वरुण धवन की फिल्म का प्रसिद्ध "वाओ" ऑडियो इस्तेमाल किया, जिसे फैंस ने काफी पसंद किया। वीडियो के साथ जान्हवी ने वरुण धवन को टैग करते हुए मजाकिया अंदाज में लिखा, "लगता है हम टकरा रहे हैं वरुण धवन।" जान्हवी के इस पोस्ट पर वरुण धवन ने भी बेहद प्यारा और दिल जीत लेने वाला जवाब दिया। उन्होंने कमेंट करते हुए लिखा, "ओह माय गॉड, तुम्हारे साथ कभी कोई क्लैश नहीं होता। तुम इस वीडियो में कमाल लग रही हो।" इसके अलावा वरुण ने जान्हवी का वीडियो अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर भी साझा किया और लिखा, "तुम्हारे साथ तो बस प्यार भरी टक्कर है जान्हवी। तुम 'पेड्डी' में बहुत शानदार लग रही हो। अपनी दोस्त को बड़े पर्दे पर देखने का मुझे बेसब्री से इंतजार है।" दोनों कलाकारों के बीच सोशल मीडिया पर हुई यह हल्की-फुल्की बातचीत फैंस को काफी पसंद आ रही है। लोग इसे बॉलीवुड में सकारात्मक रिश्तों और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का उदाहरण बता रहे हैं। वरुण धवन की फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' की रिलीज डेट को लेकर भी काफी बदलाव देखने को मिले। पहले यह फिल्म 5 जून को रिलीज होने वाली थी।

अमेरिका-ईरान संघर्षविराम पर बढ़ा दबाव, यूएई ने ड्रोन-मिसाइल हमले की पुष्टि की

दुबई। ईरान अमेरिका के बीच लागू नाजुक संघर्षविराम पर शुक्रवार को उस समय और दबाव बढ़ गया जब संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने मिसाइल और ड्रोन हमले की पुष्टि की। इससे कुछ घंटे पहले अमेरिका ने कहा था कि उसने होर्मुज जलडमरूमध्य में नौसेना के तीन जहाजों पर हुए हमलों को विफल कर दिया और जवाबी कार्रवाई में ईरानी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। ताजा हिंसा से ईरान और अमेरिका के बीच लागू संघर्षविराम पर संकट गहरा गया है, जबकि दोनों पक्ष युद्ध समाप्त करने के लिए संभावित समझौते पर विचार कर रहे हैं। तेहरान ने बृहस्पतिवार को कहा था कि वह युद्ध समाप्त करने संबंधी अमेरिका के ताजा प्रस्तावों की समीक्षा कर रहा है।

ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने कहा कि इस्लामिक गणराज्य पाकिस्तान की ओर से भेजे गए संदेशों की समीक्षा कर रहा है। पाकिस्तान शांति वार्ता में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। ईरानी सरकारी टेलीविजन के अनुसार हालांकि, ईरान अभी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा है और उसने अमेरिकी पक्ष को कोई जवाब नहीं दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की ओर से युद्ध समाप्त करने की रणनीति को लेकर मिले-जुले संकेत दिए गए हैं। पहले संघर्षविराम और सैन्य अभियान समाप्त होने की घोषणाओं के बाद अब तेहरान को यह चेतावनी दी जा रही है कि यदि उसने ऐसा समझौता स्वीकार नहीं किया जिससे तेल और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू हो सके, तो उस पर दोबारा बमबारी की जा सकती है। ट्रंप ने बृहस्पतिवार को अमेरिकी नौसेना से जुड़े घटनाक्रम के बाद इन चेतावनियों को दोहराया। उन्होंने वाशिंगटन में संवाददाताओं से कहा, "उन्हें समझना होगा कि यदि समझौते पर हस्ताक्षर नहीं हुए तो उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ेगा।" ईरान के साथ समझौते की संभावना पर पूछे गए सवाल के जवाब में ट्रंप ने कहा, "यह किसी भी दिन हो सकता है," हालांकि उन्होंने तुरंत जोड़ा, "और यह नहीं भी हो सकता है।" अमेरिका और ईरान के बीच चार अप्रैल से संघर्षविराम है।

दोनों देशों के बीच पिछले महीने पाकिस्तान की मेजबानी में हुई प्रत्यक्ष वार्ता किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी थी। यह युद्ध 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर हमले किए जाने के बाद शुरू हुआ था। यूएई के रक्षा मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी कि वे "हवा में ड्रोन मिसाइल हमले रोकने के दौरान गिरे किसी भी मलबे या टुकड़े के पास न जाएं, उसकी तस्वीर न लें और उसे न छुएं।"

इससे कुछ घंटे पहले अमेरिकी सेना ने कहा था कि उसने बृहस्पतिवार रात होर्मुज जलडमरूमध्य में नौसेना के तीन जहाजों पर हुए ईरानी हमलों को विफल कर दिया और "अमेरिकी बलों पर हमले के लिए जिम्मेदार ईरानी सैन्य ठिकानों" को निशाना बनाया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया पर कहा कि अमेरिकी बलों ने "उकसावे के बिना किए गए ईरानी हमलों" को रोका और आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की। अमेरिकी सेना ने कहा कि किसी भी जहाज को नुकसान नहीं पहुंचा और उसका तनाव बढ़ाने का इरादा नहीं है, लेकिन वह अमेरिकी बलों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है। ट्रंप ने कहा कि ताजा हिंसा के बावजूद संघर्षविराम कायम है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने बृहस्पतिवार को अपने ईरानी समकक्ष अब्बास अराघची से फोन पर बातचीत की। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की।पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने कहा, "हमें उम्मीद है कि समझौता जल्द होगा। हम आशा करते हैं कि पक्ष शांतिपूर्ण और स्थायी समाधान तक पहुंचेंगे, जिससे न केवल हमारे क्षेत्र बल्कि अंतरराष्ट्रीय शांति को भी मजबूती मिलेगी।" हालांकि, उन्होंने कोई समयसीमा बताने से इनकार किया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने टीवी पर प्रसारित बयान में कहा कि इस्लामाबाद युद्ध रोकने और युद्धविराम को आगे बढ़ाने के लिए "ईरान और अमेरिका के साथ लगातार संपर्क" में है। अमेरिका के एक अधिकारी ने नाम नहीं बताने की शर्त पर कहा कि इजराइल और लेबनान के बीच प्रत्यक्ष वार्ता अगले सप्ताह वाशिंगटन में 14 और 15 मई को होगी। इस बीच एक शिपिंग डेटा कंपनी ने बृहस्पतिवार को बताया कि ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले जहाजों की जांच और उन पर शुल्क लगाने के लिए एक सरकारी एजेंसी बनाई है। जलडमरूमध्य पर नियंत्रण को औपचारिक रूप देने की ईरानी कोशिश से अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं। फारस की खाड़ी में सैकड़ों वाणिज्यिक जहाज फंसे हुए हैं और खुले समुद्र तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। हालांकि, दो महीने से जारी संघर्ष जल्द समाप्त होने की उम्मीद से अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कुछ राहत देखी गई। शिपिंग डेटा कंपनी 'लॉयड्स लिस्ट इंटेलिजेंस' ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि ईरान ने जलडमरूमध्य से गुजरने वाले जहाजों को अनुमति देने और उनसे शुल्क वसूलने के लिए नई एजेंसी बनाई है। इससे वैश्विक व्यापार के लिए जरूरी समुद्री आवाजाही की स्वतंत्रता को लेकर चिंता बढ़ी है। 'पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी' नामक यह एजेंसी "जलडमरूमध्य से गुजरने वाले जहाजों को अनुमति देने वाली एकमात्र वैध संस्था" के रूप में खुद को स्थापित कर रही है। लॉयड्स ने कहा कि एजेंसी ने जहाजों के लिए आवेदन पत्र भी भेजा है। ईरान ने प्रभावी रूप से होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद कर रखा है, जो तेल, गैस, उर्वरक और पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण मार्ग है। वहीं, अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी कर रखी है। इससे ईंधन कीमतों में भारी वृद्धि हुई है और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा है। ईरान का उद्देश्य यह नियंत्रित करना है कि कौन से जहाज जलडमरूमध्य से गुजरेंगे और कुछ जहाजों के माल पर कर लगाया जाएगा। समुद्री कानून विशेषज्ञों का कहना है कि जहाजों की जांच और उन पर कर लगाने की ईरान की मांग अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि के तहत देशों को अपने क्षेत्रीय जल से शांतिपूर्ण आवाजाही की अनुमति देनी होती है। अमेरिका और उसके खाड़ी सहयोगी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक प्रस्ताव लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें ईरान द्वारा जलडमरूमध्य पर नियंत्रण की निंदा की जाएगी और प्रतिबंधों की चेतावनी दी जाएगी। इससे पहले जलडमरूमध्य को फिर खोलने संबंधी प्रस्ताव को रूस और चीन ने वीटो कर दिया था।

भारत ने प्रवासन प्रबंधन के लिए 'समग्र' दृष्टिकोण अपनाया है : विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह

संयुक्त राष्ट्र। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि भारत ने प्रवासन प्रबंधन के लिए एक "समग्र दृष्टिकोण" अपनाया है, जिसमें प्रवासियों के कल्याण, सुरक्षा और सशक्तिकरण को केंद्र में रखा गया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन द्वारा बृहस्पतिवार को आयोजित एक विशेष कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सिंह ने प्रवासियों की आवाजाही को सुगम बनाने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारत की "अग्रणी" डिजिटल पहल का उल्लेख किया। यह कार्यक्रम दूसरे इंटरनेशनल माइग्रेशन रिव्यू फोरम (आईएमआरएफ) के इतर आयोजित किया गया था। उन्होंने कहा, "भारतीय प्रवासन की कहानी बहुत व्यापक और गतिशील है। हमारे 3.4 करोड़ से अधिक प्रवासी दुनिया के 200 से अधिक देशों में फैले हुए हैं और हमारा वैश्विक समुदाय सदियों से अर्थव्यवस्थाओं, संस्कृतियों और विचारों को जोड़ने का कार्य करता आया है।" सिंह ने कहा कि भारतीय प्रवासी समुदाय का देश में भेजा हुआ पैसा, निवेश और ज्ञान के आदान-प्रदान के माध्यम से योगदान न केवल भारत के विकास में बल्कि उन देशों के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जहां वे रह रहे हैं। उन्होंने कहा, "पिछले कुछ वर्षों में भारत ने प्रवासन प्रबंधन के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाया है, जिसमें प्रवासियों के कल्याण, सुरक्षा और सशक्तीकरण को प्राथमिकता दी गई है।" सिंह ने संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधियों और सदस्य देशों के साथ भारत की "अग्रणी पहल" 'ई-माइग्रेट' मंच की जानकारी साझा की और बताया कि किस प्रकार भारत डिजिटल नवाचार की शक्ति का उपयोग कर रहा है।

उत्तर कोरिया सियोल को निशाना बनाने वाली नयी तोपें तैनात करेगा

सियोल। उत्तर कोरिया ने शुक्रवार को कहा कि वह इस साल लंबी दूरी की ऐसी नयी तोप प्रणालियां तैनात करेगा, जो दक्षिण कोरिया के राजधानी क्षेत्र पर हमला करने में सक्षम होंगी तथा वह आने वाले सप्ताहों में अपना पहला नौसैनिक विध्वंसक पोत सेवा में शामिल करेगा। यह घोषणा दक्षिण कोरिया के उस बयान के कुछ दिनों बाद आई है, जिसमें उसने कहा था कि उत्तर कोरिया के हाल में संशोधित संविधान में कोरियाई एकीकरण से जुड़े सभी संदर्भ हटा दिए गए हैं।

यह कदम उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन की दक्षिण कोरिया से संबंध समाप्त करने और कोरियाई प्रायद्वीप में द्विराष्ट्र व्यवस्था स्थापित करने की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। उत्तर कोरिया की सरकारी 'कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी' (केसीएनए) ने बताया कि किम ने बुधवार को एक हथियार कारखाने का दौरा किया और

155 मिलीमीटर स्वचालित तोप-होवित्जर के उत्पादन कार्य का निरीक्षण किया। इन तोपों को इस साल दक्षिणी सीमा क्षेत्र में एक तोपखाना इकाई में तैनात किया जाना है। केसीएनए ने किम के हवाले से बताया कि इस उच्च क्षमता वाली राइफल तोप की मारक क्षमता 60 किलोमीटर (37 मील) से अधिक है। किम ने कहा, "मारक क्षमता में इस तरह की तीव्र वृद्धि और उल्लेखनीय सुधार से हमारी सेना के जमीनी अभियानों में बड़ा बदलाव आएगा और उसे लाभ होगा।" किम ने कहा कि विभिन्न अभियानगत और सामरिक मिसाइल प्रणालियां तथा शक्तिशाली बहु-रॉकेट प्रक्षेपण प्रणालियां भी सीमा पर तैनात की जाएंगी। केसीएनए ने बताया कि किम ने बृहस्पतिवार को उत्तर कोरिया के पश्चिमी तट के पास विध्वंसक पोत चोह्योन पर सवार होकर उसकी संचालन क्षमता की समीक्षा की। किम ने विध्वंसक पोत के परिचालन शुरू करने से संबंधित सभी परीक्षण सुचारू रूप से होने की सराहना की और प्राधिकारियों को निर्धारित समय के अनुसार जून के मध्य में पोत को नौसेना को सौंपने का आदेश दिया। केसीएनए की तस्वीरों में किम की बेटी भी उनके साथ विध्वंसक पोत पर दिखाई दी। वह एक तस्वीर में उस समय अपने पिता के पीछे खड़ी दिखी, जब किम नौसेना के कर्मियों से बात कर रहे थे। एक अन्य तस्वीर में दोनों, पोत के चालक दल के साथ भोजन करते नजर आए। दक्षिण कोरिया की खुफिया सेवा ने पिछले महीने कहा था कि किम की बेटी को उनकी उत्तराधिकारी माना जा सकता है।

यूएई ने ड्रोन और मिसाइल हमले की सूचना दी

दुबई। संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के रक्षा मंत्रालय ने घोषणा की कि ईरान युद्ध के दौरान अस्थायी युद्धविराम को एक बार फिर चुनौती मिलने के बाद देश की हवाई रक्षा प्रणाली शुक्रवार तड़के हुए मिसाइल और ड्रोन हमले का "सक्रिय रूप से मुकाबला" कर रही है। मंत्रालय ने निवासियों को सलाह दी कि वे हवाई हमलों में गिराए गए प्रक्षेपास्त्रों के किसी भी मलबे या टुकड़ों के पास न जाएं, उनकी तस्वीरें न लें या उन्हें छुएं नहीं। इससे कुछ घंटे पहले, अमेरिकी सेना ने कहा कि उसने बृहस्पतिवार रात होर्मुज जलडमरूमध्य में नौसेना के तीन जहाजों पर ईरानी हमलों को रोका और अमेरिकी सेना पर हमला करने के लिए जिम्मेदार ईरानी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। 'यूएस सेंट्रल कमांड' ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा करते हुए कहा कि अमेरिकी सैन्य बलों ने "बिना किसी उकसावे के बावजूद किए गए ईरानी हमलों" को रोका और आत्मरक्षा में जवाबी हमले किए।

अमेरिकी संघीय अदालत ने ट्रंप के 10 % वैश्विक शुल्क को 'अवैध' बताया

वाशिंगटन। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने देश के राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास एवं कार्यालय 'व्हाइट हाउस' को एक और झटका देते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए 10 प्रतिशत वैश्विक शुल्क को "अवैध" और "कानून द्वारा अनधिकृत" करार देते हुए खारिज कर दिया है। ट्रंप द्वारा पहले लगाए गए व्यापक शुल्कों को खारिज करने के उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद अमेरिकी प्रशासन ने 24 फरवरी को भारत सहित सभी देशों पर 150 दिनों के लिए ये नए शुल्क लगाए गए थे। उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि अंतरराष्ट्रीय आपात आर्थिक शक्तियां अधिनियम (आईईईपीए) शुल्क लगाने की अनुमति नहीं देता। अमेरिका की अंतरराष्ट्रीय व्यापार न्यायालय ने बृहस्पतिवार को सुनाए फैसले में कहा कि ट्रंप ने 10 प्रतिशत शुल्क लगाने के लिए 1974 के व्यापार अधिनियम के जिन प्रावधानों का इस्तेमाल किया, वे केवल भुगतान संतुलन संकट की स्थिति में ही प्रभावी हो सकते हैं। अदालत ने एक के मुकाबले दो के बहुमत से कहा कि ट्रंप ने उस शुल्क अधिकार का अतिक्रमण किया जो संसद ने राष्ट्रपति को कानून के तहत दिया है। बहुमत ने अपने फैसले में कहा कि ये शुल्क "अमान्य" और "कानून द्वारा अनधिकृत" हैं। न्यायाधीश मार्क ए बार्नेट और क्लेयर आर केली ने अपने फैसले में कहा कि यदि राष्ट्रपति को भुगतान संतुलन घाटे की पहचान करने के लिए उप-खातों में से चयन करने की शक्ति मिल जाती है, तो जब तक प्रत्येक उप-खाता संतुलित नहीं होता, राष्ट्रपति हमेशा भुगतान संतुलन घाटा दिखा सकेंगे। दोनों न्यायाधीशों ने कहा कि कानून की "इस तरह की व्यापक व्याख्या" ट्रंप को शुल्क लगाने की वह असीमित शक्ति दे देगी, जो संसद के पास है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा की गई कानून की इस व्याख्या को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। न्यायाधीश टिमोथी सी स्टांस्यू ने अपने दोनों साथी न्यायाधीशों से असहमति जताई।